04 - भगवान के भरोसे है भारत की नागरिकता

05 - अभियान से आगे हमारी जवाबदारी का समय

06 - पुलिस मुख्यालय परिवार द्वारा 11 सेवानिवृत्त...

07 - घर-घर पहुंचकर पिलाई जा रही पोलियो की दवा

A Daily News Magazine
भोपाल
बुधवार, 01 जुलाई, 2026
भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित
वर्ष 23, अंक 299, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2
सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

बांग्लादेश-पाक की बढ़ती दोस्ती भारत के लिए चिंताजनक क्यों है?

शुभज्योति घोष

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक़ रहमान ने पद संभालने के क़रीब चार महीने बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पूरी करके देश वापसी की है। उन्होंने सबसे पहले मलेशिया का दौरा किया। इसके बाद वे चीन गए। इससे पहले काफ़ी अटकल लगाई जा रही थी कि तारिक़ रहमान पहली विदेश यात्रा भारत में करेंगे या फ़िर चीन और सऊदी अरब जैसे किसी देश में। लेकिन अंत में उन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को न चुनने का निर्णय लिया।

इत्तेफ़ाक से इस यात्रा से कुछ दिन पहले ही भारत के नए उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी बांग्लादेश पहुंचे। भारत और बांग्लादेश के बीच क़रीब 55 साल के राजनयिक संबंधों में पहली बार भारत ने किसी राजनीतिक व्यक्ति को ढाका में अपना प्रतिनिधि बनाया है। ढाका पहुंचने के तुरंत बाद उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने भूपेन हजारिका के एक लोकप्रिय गीत का हवाला दिया. इसमें यह विचार बताया गया कि दोनों देशों का 'आसमान एक है और हवा भी एक है।'

उनकी इस टिप्पणी पर बांग्लादेश में तीखी प्रतिक्रिया हुई। कई लोगों को लगा कि यह 'अखंड भारत' के विवादित विचार को बढ़ावा देने जैसा है। इसी समय दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव भी बढ़ गया है। विवाद इस आरोप को लेकर है कि भारत, लोगों को जबरन सीमा पार बांग्लादेश भेज रहा है। इस तरह की कार्रवाई को 'पुश-बैक' या 'पुश-इन' कहा जाता है।

इस मुद्दे पर हाल ही में दिल्ली में दोनों देशों की सीमा बलों के बीच एक उच्च स्तर की बैठक हुई। लेकिन इस बैठक से कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। बांग्लादेश के एक वरिष्ठ राजनयिक ने कहा, 'विदेश मंत्री खलीलुर रहमान की दिल्ली यात्रा के बाद लग रहा था कि रिश्ते फिर सामान्य हो रहे हैं। लेकिन अब वह उम्मीद लगभग ख़त्म हो गई है।'

निजी बातचीत में बांग्लादेश के अधिकारी इस नई गिरावट के लिए भारत के बीजेपी शासित दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आक्रामक रुख को जिम्मेदार मानते हैं। इनमें असम के हिमंता बिस्वा सरमा और पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी शामिल हैं। बांग्लादेश इसे उकसाने वाला और भड़काऊ मानता है।

भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मानते हैं कि हालात फिर बिगड़े हैं। लेकिन वे इसका जिम्मा पूरी तरह बांग्लादेश पर डालते हैं। उनका कहना है कि ढाका पाकिस्तान के साथ अपने संबंध मजबूत करना चाहता है। वह एक तरह का 'रणनीतिक रिश्ता' बना रहा है। यही दोनों देशों के रिश्तों में गिरावट की सबसे बड़ी वजह है।

5 अगस्त, 2024 को शेख़ हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान तेजी से करीब आए। इस दौरान पाकिस्तान के कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी बार-बार बांग्लादेश आए। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए कई नई पहलें शुरू की गईं।

दिल्ली में मौजूद भारतीय अधिकारियों ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि जब तारिक़ रहमान की अगुवाई में राजनीतिक सरकार बनेगी तो बांग्लादेश पाकिस्तान से अपनी बढ़ती नज़दीकी कम करेगा। ऐसा नहीं हुआ जिससे भारत को निराशा हुई। यह निराशा इतनी ज़्यादा थी कि भारत ने बांग्लादेश से यह अनुरोध भी नहीं किया कि तारिक़ रहमान अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा के लिए भारत आएं। फिर भी एक अहम सवाल है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो नज़दीकी दिख रही है, उसमें असली मजबूती कितनी है? भारत इसी को दोनों देशों के रिश्तों में गिरावट की वजह मानता है। क्या यह सिर्फ एक खास तरह की छवि दिखाने की कोशिश है।

बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त रहीं रीना गांगुली का बांग्लादेश में इस्लामी समूहों का बढ़ना एक बड़ा बदलाव है। हाल ही में बांग्लादेश आज़ाद पार्टी नाम के एक छोटे संगठन ने कुछ इस्लामी समूहों के साथ मिलकर ढाका में भारतीय उच्चायोग के बाहर बड़ा प्रदर्शन किया। इससे सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो गई। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ पाकिस्तान की ख़ुफ़िया एजेंसी की मदद के बिना हो सकता है। आईएसआई साफ़तौर पर बांग्लादेश में अपनी पुरानी पकड़ दोबारा मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकी की चर्चा में काफ़ी हद तक सच्चाई है। ये भारत के लिए चिंतित होने की पर्याप्त वजह है। बांग्लादेश एक बार फिर इस्लामी ताकतों के पनपने की जगह बन गया है। इसमें पाकिस्तान का मौन समर्थन भी शामिल है।

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'हम क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों को प्रभावित करने वाली हर गतिविधि पर नज़र रखते हैं।' निजी बातचीत में भारत के वरिष्ठ अधिकारी भी यही कहते हैं कि बांग्लादेश में पाकिस्तान की गतिविधियां उनकी नजर में हैं। पिछले दो वर्षों में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ संबंध मजबूत करने की जो कोशिश की है, उसका ध्यान सैन्य सहयोग पर कम, सांस्कृतिक जुड़ाव पर ज्यादा है। इसी तरह, ढाका और कराची के बीच सीधी उड़ान शुरू करने की योजना भी घोषित की गई है। भारत मानता है कि यह क़दम राजनीतिक संदेश देने के लिए ज़्यादा उठाया गया है।

भारत के नीति-निर्माण से जुड़े कई लोग आज भी बांग्लादेश के साथ रिश्तों को 1971 के मुक्ति संग्राम के नज़रिए से देखते हैं। उस इतिहास की वजह से ढाका और इस्लामाबाद के बीच सामान्य और सच्ची दोस्ती संभव नहीं है। लेकिन जब पिछले साल अगस्त में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक़ डार ढाका पहुंचे तो उन्होंने कहा कि दोनों देशों की नई पीढ़ी एक 'साझा सपना' अपनाने के लिए तैयार हैं। भारत को उम्मीद थी कि बीएनपी की सरकार आने के बाद पाकिस्तान से बढ़ती नज़दीकी कम होगी। लेकिन उसका कहना है कि ऐसा नहीं हुआ। कई भारतीय विश्लेषकों का मानना है कि कोई राजनीतिक ताक़त अगर बांग्लादेश में पाकिस्तान की स्वाभाविक सहयोगी मानी जा सकती है, तो वह जमात-ए-इस्लामी है। जो इस समय देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है।

भारत का बांग्लादेश की कूटनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था में अब भी बड़ा प्रभाव है। ऐसे में सवाल उठता है कि ढाका, पाकिस्तान के ज्यादा क़रीब दिखकर नई दिल्ली को नाराज़ क्यों करना चाहेगा? बांग्लादेश सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ पाकिस्तान की तुलना में कहीं मजबूत संबंध चाहिए। लेकिन भारत की घरेलू राजनीति की मजबूरियां रिश्तों को दूसरी दिशा में ले जा रही हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि अगर भारत उकसावे वाली बातों पर प्रतिक्रिया देने से बचे और बांग्लादेश के प्रति संतुलित और दोस्ताना नीति अपनाए, तो ढाका धीरे-धीरे खुद ही पाकिस्तान से दूरी बना सकता है।

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

सुप्रभात

मैं कुछ गुनगुनाऊँगी, अपनी ही लय में
तराने सजाऊँगी, अपनी ही लय में
तुम्हारे तराने सुरीले हैं लेकिन
नई धुन बनाऊँगी अपनी ही लय में
पहाड़ी के कोने में तनहा से मन को
मैं सरगम सुनाऊँगी, अपनी ही लय में
जो बैठा है अंतस में मुझसे लिपट कर
उसे भी रमाऊँगी, अपनी ही लय में
न कल का पता है, न साँसें ही निश्चित
समय को बहाऊँगी, अपनी ही लय में
गिराना-सताना मुझे तो न भाता
मैं जीवन सजाऊँगी, अपनी ही लय में
नए गीत-गज़लों-तरानों को बुनकर
मैं ख़ुद डूब जाऊँगी, अपनी ही लय में।

- डॉ. सीमा विजयवर्गीय

राम मंदिर चढावा चोरी मामला : अयोध्या पहुंचे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष किए गए नजरबंद

● कई कांग्रेस नेता हाउस अरेस्ट, सीसीटीवी की निगरानी में तैनात अफसर का 17 साल बाद ट्रांसफर

अयोध्या (एजेंसी)। अयोध्या में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को नजरबंद कर दिया गया है। विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में धक्का-मुक्की हुई।

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने सोमवार देर रात 11.30 बजे अयोध्या के एक होटल में नजरबंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उन्हें कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस ले गई।

कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा, तनुज पूनिया और उज्जवल रमण सिंह को हाउस अरेस्ट किया गया है। अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस डेलिगेशन चढ़ावा चोरी का विरोध करने पहुंचा था। उन्होंने आज यानी मंगलवार को ट्रस्ट कार्यालय के घेराव का ऐलान किया था।

इस बीच, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोपहर 12.30 बजे राम जन्मभूमि मंदिर कूच किया। पुलिस ने मंदिर से एक किलोमीटर पहले टेढ़ी बाजार में उन्हें रोक दिया। इससे कार्यकर्ता भड़क गए। धक्का-मुक्की करने लगे। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें हिरासत में लिया। घसीट-घसीटकर गाड़ी में भरा।

इससे पहले, अजय राय की पत्नी रीना राय ने वाराणसी से एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा- मेरे पति की आवाज दबाने के लिए भाजपा सरकार किसी भी हद तक गिर सकती है। पुलिस जीप में ले जाने के बाद हमारे सहयोगियों को गलत जानकारियां देकर भटकाया जा रहा है।

चंपत राय से 3 घंटे पूछताछ

सरकार ने एसआईटी से फाइनल रिपोर्ट मांगी

चंपत राय से रविवार को पुलिस ने करीब 3 घंटे पूछताछ की। पूछा कि उन्हें चढ़ावा चोरी का पता पहली बार कब और कैसे लगा। उसके बाद क्या-क्या किया। इससे पहले, कोर्ट ने सोमवार को चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी। सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने एसआईटी से फाइनल रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपने को कहा है। चोरी का मामला पहली बार 7 जून को सामने आया था। यूपी सरकार ने 13 जून को एसआईटी बनाई। वहीं चंपत राय ने कहा हाँ कहीं न कहीं हमसे गलती हुई। हम इसे स्वीकारते हैं। वहीं रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन

जल संरक्षण में प्रदेश बना नंबर वन, सीएम ने कहा- जल के बिना जीवन नहीं

भोपाल/राजगढ़ (नप्र)। एमपी में जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन हो गया है। इसे लेकर राजगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सीएम मोहन यादव ने इस मौके पर कहा कि जल संरक्षण में एमपी नंबर वन है। साथ ही राजगढ़ जिले को 352.65 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। उन्होंने दिव्यांगों को ट्राइसाइकल भी दिए हैं।

सीएम ने भैंसवामाता क्षेत्र स्थित पवित्र दूध तलैया में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा-अर्चना की, साथ ही गौ माता को गुड़ और हरी घास खिलाई। उन्होंने भैंसवामाता और माता बिजासन से प्रदेश की सुख-समृद्धि-जनकल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजगढ़ के सारंगपुर में जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन समारोह में कन्या-पूजन किया। मुख्यमंत्री ने जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन समारोह में रिमोट से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजगढ़ के सारंगपुर में जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन समारोह में हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए। इस दौरान उन्होंने हरित भारत का संदेश भी दिया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ने भैंसवामाता मंदिर के प्रस्तावित स्वरूप का अवलोकन किया और विकास सहित सौंदर्यीकरण से संबंधित प्रस्तावित कार्यों की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर उन्होंने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।

जल संरक्षण में राजगढ़ बना अग्रणी

कपिल मुनि की तपोस्थली राजगढ़ जिला जल संचय के कार्यों में अग्रणी बना है। यह जल गंगा संवर्धन अभियान-2026 के अंतर्गत श्रेष्ठ कार्य करने वाले 6 जिलों में शामिल है। राज्य सरकार ने 19 मार्च से 30 जून तक 100 दिन के अभियान में कुएं, बावड़ी, तालाब, नदियों, अमृत सरोवर और प्राचीन जल स्त्रोतों के जीर्णोद्धार का संकल्प लिया। जल गंगा संवर्धन अभियान-2026 में लगभग 10 हजार करोड़ लागत से 3 लाख 62 हजार के अधिक जल स्त्रोतों का पुनरोद्धार किया गया है।

सीएम ने इस दौरान विकास कार्यों का भूमि-पूजन कर शिलान्यास और लोकार्पण किया। इससे पहले सीएम डॉ. मोहन यादव का यहां पारंपरिक स्वागत किया गया। मंदिर के प्रवेश द्वार पर आदिवासी नृत्य दल ने पूरे उत्साह, उमंग और जोश के साथ अपनी आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। बच्चियों ने सिर पर कलश धारण कर पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार उनका आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिव्यांगजनों को मोटोराइज्ड ट्राईसाइकिल की चाबियां वितरित कर उन्हें आत्मनिर्भरता की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने ब्यावरा की पर्यावरण प्रेमी संरक्षण समिति द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट से तैयार किए जा रहे ईको ब्रिक्स की सराहना की।

पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं

● प्रदर्शनकारियों ने इस्लामाबाद को दी चेतावनी, हम भारत से जुड़ जाएंगे

इस्लामाबाद(एजेंसी)। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलकोट में हजारों लोग पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी इस इलाके में सरकार के कंट्रोल का विरोध कर रहे हैं। बीते 22 दिनों से रावलकोट में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है।

ईदगाह ग्राउंड में हुए प्रदर्शन के दौरान, वक्ताओं ने कहा कि इस इलाके को अब पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं माना जाना चाहिए। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी दी कि वो भारत के साथ जुड़ जाएंगे।

'भूखे मरे तो खोल देंगे भारत की सीमा', पाकिस्तानी सेना की नाकेबंदी से भड़की आग, - क्या पाकिस्तान के नक्शे से पीओजेके यानि अवैध कब्जे वाला कश्मीर हमेशा के लिए हटने वाला है? रावलकोट के ईदगाह मैदान से आई एक गूंज ने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी है। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओजेके में भारी विद्रोह फूट पड़ा है। हजारों लोग पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पीओजेके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और वो पाकिस्तानी सेना के जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

रावलकोट के ईदगाह मैदान से उठी एक गूंज ने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय तक हड़कंप मचा दिया है।

बोरवेल में गिरा मासूम निरवैर को बचाने की जंग तेज

● बारिश के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन था जारी

अंबाला (एजेंसी)। हरियाणा के अंबाला स्थित गांव धन्यौड़ा में एक 4 वर्षीय मासूम बच्चा खेलते-खेलते 220 फुट गहरे बोरवेल में गिर गया। वहीं बच्चे को बचाने के लिए एनडीआरएफ एवं भारतीय सेना कड़ी मशक्कत कर रही है। बच्चे को किसी तरह बचाकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। बोरवेल में गिरे निरवैर तक प्रशासन का डाले कैमरे से एक तस्वीर भी सामने आई है। कैमरे में बच्चे का एक हाथ दिखाई दे रहा है।

निरवैर सिंह अपने चाचा हरनेक सिंह के खेत में खेल रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह खुले पड़े ट्यूबवेल के गहरे बोरवेल में जा गिरा। बोरवेल में गिरे मासूम निरवैर को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रशासन और रेस्क्यू टीमें दिन-रात एक किए हुए हैं। बच्चे को बचाने के लिए पुरजोर कोशिशें की जा रही है।

● **रिसाव बना मुसीबत....मौके पर पहुँची हैवी मशीनें**- ऑपरेशन को तेज करने के लिए विशेष बोरवेल और हैवी एक्सकेवेटर मशीनें मौके पर मंगवाई गई हैं। हालांकि, रेस्क्यू ऑपरेशन में प्राकृतिक बाधाएं भी सामने आ रही हैं। बोरवेल के अंदर पानी का लगातार हो रहा रिसाव बचाव दल के लिए इस समय सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है।

● **अंदर की विजिबिलिटी काफी कम** - लगभग 220 फीट की गहराई पर पानी रिसने की वजह से अंदर की विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिससे रेस्क्यू टीम को दिक्कत आ रही है। कैमरे के जरिए बच्चे पर नजर रखी जा रही है, हालांकि अभी तक बच्चे के साथ कोई संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है। कैमरे में बच्चे का एक हाथ दिखाई दे रहा है।

● **बोरवेल के समानांतर एक और गहरा गड्ढा खोदा जा रहा था**- मासूम निर्भय को सुरक्षित निकालने के लिए तय रणनीति के तहत बोरवेल के समानांतर एक और गहरा गड्ढा खोदा जा रहा है। इसके लिए प्रशासन ने बिना वक्त गंवाए बड़ी बोरवेल और अत्याधुनिक खुदाई मशीनें तैनात कर दी हैं। मिट्टी धंसने के खतरे को देखते हुए बेहद सावधानी से खुदाई की जा रही है।

ऑक्सीजन और मेडिकल टीम मौके पर मुस्तैद थी

बोरवेल के अंदर फंसे निर्भय तक लगातार पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। एक विशेष मेडिकल टीम एम्बुलेंस के साथ मौके पर तैनात है, जो कैमरे के माध्यम से बच्चे की हर हरकत और सेहत पर नजर रखे हुए है। बच्चे के माता-पिता और पूरा इलाका निर्भय की सलामती के लिए दुआएं मांग रहा है। मिली जानकारी के अनुसार, 4 वर्षीय निरवैर सिंह सुबह करीब साढ़े छह बजे अपने पिता, चाचा और चचेरे भाई के साथ खेत पर घूमने गया था। वह अपने चाचा हरनेक सिंह के खेत में खेल रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह खुले पड़े ट्यूबवेल के गहरे बोरवेल में जा गिरा।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c | न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

भोपाल ■ बुधवार, 01 जुलाई 2026

हरदा में चलती स्कूल वैन में लगी आग

बच्चों को छोड़कर लौट रही थी, आस पास के लोगों ने रेत डालकर पाया काबू

हरदा (नप्र)। हरदा में मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे छीपानेर रोड स्थित आयकर विभाग कार्यालय के सामने एक वैन में अचानक आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों और वाहन चालक ने तुरंत आग बुझाने की कोशिश की। इससे बड़ा हादसा टल गया। आग लगने के दौरान केवल ड्राइवर वाहन में सवार था। वैन बच्चों को छोड़कर लौट रही थी।

खड़ी वैन से उठने लगा धुआं- जानकारी के अनुसार, प्रेस लिखी यह वैन स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने का काम करती है। वैन एक पिज्जा दुकान के पास खड़ी थी। इसी दौरान उसमें से धुआं निकलने लगा। कुछ ही देर में आग की लपटें उठने लगीं। गनीमत रही कि घटना के समय वैन में कोई बच्चा सवार नहीं था। लोगों ने रेत की मदद से आग पर काबू पा लिया।

घटना के बाद लोगों की लगी भीड़- आग लगने की सूचना मिलते ही सड़क पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। घटना के बाद शहर के युवा समाजसेवी शुभम सुरमा ने ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ विभाग से स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने वाले सभी वाहनों की जांच कराने की मांग की। उन्होंने कंडम वाहनों के संचालन पर रोक लगाने की भी बात कही।

आरटीओ राकेश आहके ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि जल्द ही स्कूली बच्चों के लिए उपयोग में आने वाले सभी वाहनों की जांच की जाएगी। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी।

300 किमी पैदल भोपाल पहुंचे दो कांग्रेसी

पीसीसी के सामने धरने पर बैठे, बोले- एक व्यक्ति को तीन-चार पद का विरोध किया तो निष्कासित कर दिया

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जिला कांग्रेस कमेटियों की लिस्ट घोषित होने के साथ ही विरोध के स्वर उठ रहे हैं। भोपाल की जिला कांग्रेस कमेटी पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सवाल खड़े किए हैं तो वहीं रतलाम की जिला कांग्रेस कमेटी में एक-एक व्यक्ति को तीन-चार पद देने का विरोध करने पर दो कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया।

दोनों ही कांग्रेस कार्यकर्ता रतलाम से तीन सौ किलोमीटर पैदल चलकर आठ दिन का सफर तय कर भोपाल पहुंचे और पीसीसी यानी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। कांग्रेस के निष्कासित दोनों कार्यकर्ताओं ने मीडिया से बातचीत की।

पीसीसी के सामने धरने पर बैठे संजय रावल ने कहा- हम दोनों यह पैदल यात्रा करते हुए भोपाल आए हैं। हम दोनों को संगठन महासचिव द्वारा निष्कासित किया गया है उसके पास ऐसा कोई पावर नहीं हैं कि वो हमें निष्कासित करे। हम कांग्रेस कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं जीतू पटवारी यहां आए और हमसे बिना बातचीत किए ही चले गए।

जिला कार्यकारिणी पर सवाल उठाए

रतलाम से आए कांग्रेस के निष्कासित कार्यकर्ता गौरव पोरवाल ने मीडिया को बताया कि हम तीन सौ किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए भोपाल आए हैं। गौरव ने बताया हम इसलिए आए हैं क्योंकि अभी रतलाम की जिला कार्यकारिणी बनी थी तो किसी को तीन पद दे दिए, किसी को चार पद दे दिए तो हमने सोशल मीडिया और व्यक्तिगत रूप से जिला अध्यक्ष जी को मैसेज पहुंचाया था कि आप संगठन में एक व्यक्ति को तीन चार पद दे रहे हैं तो ये शोभा नहीं देता।

हमारी जिलाध्यक्ष से बात हुई थी। वे कह रहे थे हमारे पास कार्यकर्ता नहीं हैं। कांग्रेस की इतनी स्थिति खराब हो गई है कि नए कार्यकर्ता नहीं मिल रहे इसलिए आप एक-एक व्यक्ति को तीन-तीन पद दे रहे हो।

निष्कासित कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि जीतू पटवारी से 4 जून को उन्होंने नामली में मुलाकात की थी। उन्होंने हमें गले लगा लिया था इसके बाद जिला कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया।

जीतू पटवारी से मिले तो जिला कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया

गौरव ने बताया 4 जून को नामली में हम यही दरी लेकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के पास गए थे। उनसे बात की तो उन्होंने हमें गले लगाया और साथ में बिठाकर लेकर गए थे। उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी को प्रदेश अध्यक्ष से मिलना इतना बुरा लगा कि हमें पार्टी से निष्कासित कर दिया। उन्होंने हमारे पर आरोप लगाया लेकिन उनके पास ठोस सबूत आज भी नहीं हैं कि किस कारण से निष्कासित किया है।

संक्षिप्त समाचार

जनरल धीरज सेठ ने नए सेनाध्यक्ष का कार्यभार संभाला

नई दिल्ली (एजेंसी)। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी जनरल धीरज सेठ ने मंगलवार को नए सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया। उनके नाम पश्चिमी मोर्चे पर सेना की दो अभियानगत सैन्य कमान के नेतृत्व की विशिष्ट उपलब्धि दर्ज है। जनरल सेठ ने 13 लाख

सैनिकों वाली सेना की कमान ऐसे समय में संभाली है जब वह सीमाओं पर चुनौतियों का सामना करते हुए खुद को आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। जनरल सेठ ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह ली है जो सशस्त्र बलों में 40 साल से अधिक के शानदार करियर के बाद मंगलवार को सेवानिवृत्त हुए। जनरल सेठ राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए), खड़कवासला के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में 'आर्मर्ड कोर' में शामिल किया गया था. 31वें सेनाध्यक्ष (सीओएएस) बनने से पहले उन्होंने उप सेना प्रमुख के तौर पर सेवाएं दी थी।

अखिलेश ने विधायक कमाल अख्तर से कहा-इस्तीफा दे दो

लखनऊ (एजेंसी)। मुरादाबाद के विधायक कमाल अख्तर ने विधानसभा में समाजवादी पार्टी के दल के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। यह

फैसला मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा के साथ विवाद सामने आने के बाद आया है। हालांकि इस्तीफे के कारणों पर पार्टी की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। विवाद को सुलझाने के लिए हाल ही में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में दोनों पक्षों के साथ बैठक भी की थी। माना जा रहा था कि मामला शांत हो गया है, लेकिन अब कमाल अख्तर के इस्तीफे ने अटकलों को फिर हवा दे दी है।

बंगाल से कश्मीर तक 1500 किमी लंबी मानसून पट्टी

नईदिल्ली/भोपाल/जयपुर/लखनऊ/पटना (एजेंसी)। मानसून ने मंगलवार 30 जून दोपहर जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश में एंट्री कर ली है। देश में अब तक 26 राज्यों को कवर कर लिया है। इससे पहले 24 जून को मध्य प्रदेश-गुजरात में एंट्री ली थी। इसके बाद 6 दिन अटका रहा। इससे कई राज्यों में गर्मी और उमस बनी हुई है। उधर, दिल्ली और उत्तर भारत के लिए राहत की खबर

आ रही है। सैटेलाइट तस्वीरों में करीब 1,500 किमी लंबी मानसून ट्रफ (कम दबाव की लंबी पट्टी) बनती हुई दिखाई दी है। यह उत्तरी बंगाल की खाड़ी से लेकर जम्मू-कश्मीर तक फैली हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, मॉनसून ट्रफ बन चुकी है, लेकिन फिलहाल यह हिमालय की तलहटी (फुटहिल्स) के करीब स्थित है। यह ट्रफ धीरे-धीरे दक्षिण की ओर अपनी सामान्य स्थिति में पहुंचेगी, उत्तर भारत में बिहार, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर 1 से 4 जुलाई के बीच भारी बारिश हो सकती है।

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन समारोह में हुए शामिल

उप मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाने का किया आह्वान

भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने ग्राम पंचायत कोठी में आयोजित जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, ग्रामीणों, महिलाओं, युवाओं एवं विद्यार्थियों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि जल केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि जीवन, विकास और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा का आधार है। इसलिए जल संरक्षण को जनभागीदारी के माध्यम से जनआंदोलन का स्वरूप देना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से प्रेरित होकर प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान को व्यापक जनसहभागिता के साथ संचालित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य केवल शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक को जल संरक्षण के प्रति जागरूक और सहभागी बनाना है। मध्यप्रदेश नदियों, तालाबों, कुओं एवं प्राकृतिक जल स्त्रोतों से समृद्ध

प्रदेश है, लेकिन बदलते जलवायु चक्र, भूजल के अत्यधिक दोहन तथा जल के अनियंत्रित उपयोग के कारण जल संरक्षण की चुनौती लगातार बढ़ रही है। ऐसे में आधुनिक तकनीकों और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से जल स्त्रोतों का संरक्षण एवं संवर्धन आवश्यक है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जिले सहित प्रदेश भर में जल संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़े लाखों कार्य किए गए हैं। खेत तालाब, कुओं का रिचार्ज, अमृत सरोवर, चेकडैम निर्माण, नालों की सफाई, वर्षा जल संचयन, जल गुणवत्ता परीक्षण तथा नदी संरक्षण जैसे कार्यों से जल संसाधनों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं। साथ ही विद्यालयों, आंगनवाड़ियों और ग्रामीण समुदायों में जल संरक्षण के प्रति व्यापक जनजागरण भी किया गया। उप मुख्यमंत्री ने जल गंगा संवर्धन अभियान को सफल बनाने वाले सभी विभागों, पंचायत प्रतिनिधियों, नगरीय निकायों, स्वयंसेवी संगठनों, किसानों, महिलाओं, युवाओं एवं आम नागरिकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक अपने घर, गांव और आसपास के जल स्त्रोतों की स्वच्छता एवं संरक्षण का दायित्व निभाए तथा जल का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करे। उन्होंने आगामी मानसून में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान करते हुए कहा कि जल संरक्षण और वृक्षारोपण एक-दूसरे के पूरक हैं। जहां हरियाली होगी, वहीं जल संरक्षण भी प्रभावी होगा। प्रत्येक परिवार कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए और उसके संरक्षण का संकल्प भी ले। कार्यक्रम के अंत में उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने सभी उपस्थित नागरिकों से जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाकर प्रदेश को जल समृद्ध, हरित और विकसित बनाने में सक्रिय सहभागिता निभाने का आग्रह किया। इस अवसर पर सांसद श्री जनार्दन मिश्र, प्रभारी कलेक्टर अक्षत जैन, सीईओ जिला पंचायत मेहताब सिंह गुर्जर, एसडीएम अनुराग तिवारी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

'बदलूराम का बदन' जमीन के नीचे

दूर देश सेशेल्स में यह गीत सुनकर पीएम मोदी भी गर्व से खड़े हो गए

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सेशेल्स के दौरे पर थे तो 29 जून को सेशेल्स का 50वां राष्ट्रीय दिवस समारोह मनाया गया था। पूर्वी अफ्रीकी द्वीपीय देश सेशेल्स का राष्ट्रीय दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस हर साल 29 जून को मनाया जाता है। यह दिन 1976 में यूनाइटेट किंगडम से सेशेल्स की स्वतंत्रता की याद दिलाता है। इस मौके पर असम रेजिमेंट का चर्चित रेजिमेंटल गीत 'बदलूराम का बदन' गीत गाया गया। पीएम के सामने जब असम रेजिमेंट का जब यह गीत गाया गया तो वह गर्व से खड़े हो गए। उन्होंने इसका जिक्र भी सोशल मीडिया एक्स पर किया है। जानते हैं कौन थे बदलूराम, जिन पर बना था यह मशहूर गीत।

जब पूरे सेशेल्स में गूंज उठा 'बदलूराम का बदन' गीत

सेशेल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान असम रेजिमेंट के जवान और नौसेना का बैंड भव्य परेड में शामिल हुए और भारतीय नौसेना के दो जहाज स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तरकश और सर्वे वेसल आईएनएस इक्षक ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मार्च करते समय सेना की टुकड़ी ने असम रेजिमेंट का रेजिमेंटल गीत 'बदलू राम का बदन' गाया। पीएम मोदी ने 29 जून को ट्वीट कर कहा-कल सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में असम रेजिमेंट और भारतीय नौसेना की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। यह भारत और सेशेल्स के बीच गहरी दोस्ती का एक और उदाहरण था। जब सेशेल्स में यह गीत गाया गया तो पीएम मोदी भी यह देखकर अभिभूत हो गए और गर्व से तनकर खड़े हो गए।

क्या छिड़ेगी नई जंग?

ईरानी सेना आईआरजीसी और अमेरिकी हथियारों से लैस कुर्दों के बीच सीमा पर खूनी झड़प

रियाद (एजेंसी)। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर के बाद अब एक और जंग का खतरा मंडराने लगा है। हाल के दिनों में कई ईरानी सैनिक सीमा पर हुए संघर्ष में मारे गए हैं। ईरान के शफाक न्यूज ने 30 जून को खुलासा किया कि देश के पश्चिमी और पश्चिमोत्तर इलाके में मंगलवार को दो अलग-अलग घटनाओं में 4 ईरानी सैनिक मारे गए हैं। वहीं ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर की करीबी तसनीम न्यूज एजेंसी ने भी खबर दी है कि आईआरजीसी के दो सदस्य

मारे गए हैं और 2 अन्य घायल हो गए हैं। न्यूज एजेंसी ने बताया कि यह हथियारबंद आतंकी हमला था जो केरमानशाह प्रांत में सीमाई शहर पावेह में किया गया था।

इजरायली अखबार यरुशलम पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि ईरान के कुर्दिस्तान प्रांत के बानेह शहर के अंदर गोलीबारी की घटना हुई है। एक बंदूकधारी ने एक पुलिस चेकप्वाइंट को निशाना बनाया। इस हमले में दो पुलिसकर्मी मारे गए हैं और 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं।

क्या ई20 पेट्रोल आपकी कार को कर देगा बेकार

सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ जो डर गई सरकार, कहा अभी परीक्षण के दौर में है

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश में जब से सरकार ने एथेनॉल मिले हुए पेट्रोल सप्लाई शुरु करने का फैसला लिया तभी से आम जनता के मन में अपने वाहनों को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं भी आईं हैं। सबसे बड़ा डर कि क्या ई20 पेट्रोल हमारी कार को कर देगा बेकार? इन आशंकाओं के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल, ई20 मिश्रण की नीति का प्रभाव अभी परीक्षण के दौर में है और इसके परिणाम अगले वर्ष तक साफ होंगे। सरकार ने यह भी बताया कि ई20 नीति वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि यह राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति का हिस्सा है।

● **सुप्रीम कोर्ट में एथेनॉल पर सुप्रीम विवाद-** मामले की शुरुआत विन्प डिस्टिलरीज एंड शुगर प्राइवेट लिमिटेड कपनी की याचिका से जुड़ा है। कंपनी ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए दलील दी थी कि वह एथेनॉल बनाती है। सरकार की ओर से उसे केवल 3.92 करोड़ लीटर का आवंटन किया गया है जबकि उसने 9.26 करोड़ लीटर की बोली लगाई थी। मामले में सरकार की ओर से कहा गया कि किसी भी कंपनी को पहले ज्यादा आवंटन मिला तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि कंपनी को हर बार उतनी ही मिलेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार को अपने आवदेन पर फिर से विचार करने को कहा था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

सुप्रीम कोर्ट में सरकार की आशंकाएं

- सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा कि ई20 ब्लेंडिंग प्रोग्राम अभी प्रायोगिक फेज में है।
- इसके अच्छे बुरे नतीजे अगले साल तक सामने आएंगे। अभी यह कहना कि इससे वाहन खराब होने की धारणाएं निर्मूल हैं।
- फिलहाल ई20 नीति में बदलाव की कोई योजना नहीं है। एथेनॉल का आवंटन मांग और उपलब्धता के आधार पर घट-बढ़ सकता है। मौजूदा सप्लाई नीति जारी रहेगी।
- अगर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार किसी एक सप्लायर का कोटा बढ़ाते, तो वैसे में कानूनी विवादों का सिलसिला शुरू हो जाता और फिर सप्लाई चेन ध्वस्त हो जाती।
- सरकार की ओर से यह भी आशंका जतायी गई कि अलग-अलग हाईकोर्ट में इस मुद्दे से जुड़ी कई याचिकाएं लंबित हैं, जिससे राष्ट्रीय नीति प्रभावित हो सकती है।

97वीं ऑपरेशन एंड को-ऑर्डिनेशन कमेटी की राज्य स्तरीय बैठक संपन्न

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सोमवार को भोपाल में 97वीं ऑपरेशन एंड को-ऑर्डिनेशन कमेटी की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान राज्य विद्युत ग्रिड के सुरक्षित, विश्वसनीय एवं समन्वित संचालन, विद्युत मांग-आपूर्ति प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा के प्रभावी एकीकरण, ग्रिड अनुशासन, ट्रांसमिशन समन्वय तथा मध्य प्रदेश विद्युत ग्रिड कोड के विभिन्न प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। इसके साथ ही विभिन्न परिचालन संबंधी मुद्दों पर उपयोगी सुझाव एवं निर्णय लिए गए, जिनसे प्रदेश की विद्युत प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ एवं दक्ष बनाने में सहायता मिलेगी।

स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के मुख्य अभियंता श्री प्रदीप सचान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के निदेशक (वाणिज्य एवं तकनीकी) श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) डॉ. राकेश शर्मा, उप मुख्य महाप्रबंधक (संचालन एवं संधारण) श्री शिशिर गुप्ता, महाप्रबंधक (ऑपरेशन) श्री संजीव कुमार कुशवाहा, सहायक अभियंता श्री स्वप्निल खम्पारिया, उप महाप्रबंधक भोपाल दक्षिण शहर संभाग श्री राकेश त्रिपाठी, वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी श्री मनोज द्विवेदी, सहायक अभियंता श्री ऋषि तिवारी सहित एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी एमपी पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी एमपी पॉवर जनरेटिंग कंपनी, प्रदेश की सभी विद्युत वितरण कंपनियों, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों, अडाणी पॉवर, मेघा इंजीनियरिंग, रेलवे तथा विद्युत क्षेत्र से जुड़े अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने सक्रिय रूप से सहभागिता की। इस अवसर पर बैठक की कार्यवाही का संचालन ऑपरेशन एंड को-ऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी श्री विवेक कुमार अग्रवाल ने एवं कार्यक्रम संचालन महाप्रबंधक (संचालन एवं संधारण) श्री संजीव कुशवाहा एवं सहायक अभियंता सिविल सुश्री हिमांशी पांडे ने किया। बैठक के सफल आयोजन पर सभी सहभागी संस्थाओं ने मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा की गई उत्कृष्ट व्यवस्थाओं एवं समुचित समन्वय की सराहना की।

एसबीआई को 1,266 करोड़ के नुकसान पर ईडी की कार्रवाई

3.66 करोड़ की बीमा पॉलिसी कुर्क, कंपनी प्रमुख ने विदेशी बैंक खातों से ली थीं

भोपाल (नप्र)। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को फर्जी मर्चेंटिंग ट्रेड लेन-देन के जरिए 1,266.63 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मेसर्स एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (एओपीएल) और उसके सूत्रधार श्रीकांत भासी से जुड़ी 3.66 करोड़ रुपए की निवेश आधारित जीवन बीमा पॉलिसियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। ईडी के अनुसार कुर्क की गई दो इन्वेस्टमेंट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों का सरेंडर मूल्य 3,87,814.42 अमेरिकी डॉलर (करीब 3.66 करोड़ रुपए) है। ये पॉलिसियां ज्यूरिख इंटरनेशनल लाइफ लिमिटेड में संचालित थीं और इन्हें विदेशी बैंक खातों के माध्यम से खरीदा गया था। यह कार्रवाई सीबीआई, बीएसएफसी नई दिल्ली द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है।

फर्जी दस्तावेजों और हवाला के जरिए धन का लेन-देन- ईडी की जांच में सामने आया कि कंपनी और उसके प्रवर्तकों ने कथित रूप से फर्जी व्यापारिक दस्तावेज, बैंकिंग सुविधाओं के दुरुपयोग, सिक्योरिटी ट्रेडिंग और हवाला माध्यमों से धन का देश-विदेश में ट्रांजेक्शन किया।

प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विवि के विषय विशेषज्ञों ने दिए टिप्स

भोपाल। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में प्रजापिता ब्रम्हकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा 'स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिजिटल वेलबीइंग, डीट्वएडिक्शन और वेल्यू बेस्ड एजुकेशन' विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नालंदा पुस्तकालय में आयोजित कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियो ने भाग लिया। इस अवसर पर लेखक एवं इमोशनल एक्सपर्ट हितेश टुटेजा ने अपने व्याख्यान में कहा कि आजकल हम प्रकृति से दूर हो गए हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने आपको बदलना है। शिक्षक के रुप में हमें बच्चों से इमोशनली कनेक्ट होना है। हमें जो भी कार्य करना है, खुश होकर करना है। हमें अपने आपको अंदर से जानने एवं पहचानने की जरुरत है। इसके पश्चात ईश्वरीय विश्वविद्यालय भोपाल से हेमा दीदी ने मेडिटेशन करवाया। कार्यक्रम में ईश्वरीय विश्वविद्यालय से ममता दीदी, नारायण जी भी उपस्थित थे। इस आयोजन में एमसीयू की कुलसचिव प्रो. डॉ. पी. शशिकला, वित्त नियंत्रक राजेश सिंह समेत कई अधिकारी एवं शिक्षक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संयोजन जनसंचार विभाग के अध्यक्ष प्रो. डॉ.संजय द्विवेदी ने किया, जबकि संचालन मीडिया प्रबंधन विभाग के अध्यक्ष प्रो. डॉ. अविनाश वाजपेई द्वारा किया गया।

मुख्यमंत्री ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्व. रोहाणी की जयंती पर किया नमन

विधानसभा के सेंट्रल हाल में अर्पित की पुष्पांजलि

फोटो: प्रवीण वाजपेई

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्व. ईश्वर दास रोहाणी की जयंती पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंगलवार को विधानसभा के सेंट्रल हाल में स्व. रोहाणी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुष्पांजलि कार्यक्रम के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा में कहा कि विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर के द्वारा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्षगण की जयंती व पुण्यतिथि के अवसर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन अनुकरणीय पहल है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्व. रोहाणी एक जननेता थे, उन्होंने अपने राजनैतिक जीवन का पहला चुनाव वर्ष 1993 में जबलपुर से लड़ा। इसके बाद उनके विधायक निर्वाचित होने का सिलसिला चलता रहा और श्री रोहाणी ने लगातार 4 विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। उन्होंने जबलपुर की जनता के लिए संपूर्ण त्याग और समर्पण के साथ जनहितैषी कार्यों को आगे बढ़ाया। वे कर्मठ, स्पष्टवादी जनप्रतिनिधि होने के साथ एक आदर्श विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। जनसेवा, लोकतांत्रिक मूल्यों और संगठन निर्माण के प्रति श्री रोहाणी का अद्वितीय योगदान प्रदेशवासियों के लिए सदैव प्रेरणादायी रहेगा।

मप्र में पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने के आदेश

महाधिवक्ता की कानूनी राय के बाद पत्र जारी, कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन होंगे प्रमोशन

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। करीब एक दशक से रुकी पदोन्नति (प्रमोशन) प्रक्रिया अब शुरू होने की तैयारी में है। सामान्य प्रशासन विभाग (डीएडी) ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को पत्र जारी कर प्रमोशन प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में महाधिवक्ता की कानूनी राय के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने यह कदम मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 को लेकर लंबित याचिकाओं के बीच उठाया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि महाधिवक्ता ने वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन की कानूनी राय भेजी है। इसी के आधार पर विभागों को आगे की कार्रवाई करने को कहा गया है।

क्या है कानूनी राय- वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने अपनी राय में कहा है कि हाईकोर्ट ने प्रमोशन नियम-2025 पर कोई अंतरिम रोक (स्टे) नहीं लगाई है। पहले राज्य सरकार ने सुनवाई के दौरान अनौपचारिक रूप से प्रमोशन नहीं करने का आश्वासन दिया था, लेकिन वह न तो कोर्ट के आदेश का हिस्सा था और न ही किसी न्यायिक रिकॉर्ड में दर्ज है। अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं क्योंकि मामला नए सिरे से सुनवाई के लिए जाएगा। इसलिए सरकार अपने वैधानिक अधिकारों का उपयोग कर सकती है।

राम मंदिर दान चोरी पर धीरेंद्र शास्त्री बोले

आस्था और सनातन परंपरा को ठेस लगी, महादंड मिलेगा

भोपाल में कहा- भारत के मुसलमान इंडोनेशिया जाकर देखें, नमाज पढ़ने वाले दिवाली मनाते हैं

भोपाल (नप्र)। भोपाल में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मंगलवार को राम मंदिर से जुड़े हालिया विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस घटना से लाखों-करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और सनातन परंपरा से जुड़े लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।

धीरेंद्र शास्त्री के मुताबिक, यह सिर्फ एक मंदिर का मामला नहीं, बल्कि पूरे सनातन समाज की प्रतिष्ठा और विश्वास से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि भगवान राम के धाम में रहकर इस तरह का कृत्य करने वालों को महादंड मिलेगा।

धर्म विरोधी ताकतें ऐसी परिस्थितियां बना रही हैं- राम मंदिर चंदा चोरी मामले में संघ और चंपत राय का नाम आने तथा उन पर एफआईआर दर्ज नहीं होने के सवाल पर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। एसआईटी और जांच एजेंसियां लगी हैं, इसलिए उन्हें निष्पक्ष जांच करने दी जानी चाहिए। विदेशों में इस मामले की आलोचना पर उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा को मानने वाले लोगों के मन में यह पीड़ा है। उन्होंने बताया कि जकार्ता में भी मैंने इस विषय का जिक्र किया था।

सभी मंदिरों को शंकराचार्य के नियंत्रण में देने के सवाल पर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि धर्म विरोधी ताकतें ऐसी परिस्थितियां बना रही हैं, जिससे मंदिरों और संतों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मंदिरों की सेवा और प्रबंधन की जिम्मेदारी ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए, जो सनातन, वैष्णव परंपरा और भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित हों।

सिया-केतन केस पर बोले- अपराध की जड़ संस्कारों की कमी

पुणे के चर्चित सिया-केतन केस पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा- बढ़ते अपराधों के पीछे संस्कारों का अभाव सबसे बड़ा कारण है। कानून केवल दंड दे सकता है, लेकिन समाज को सही दिशा संस्कार ही दे सकते हैं। यह घटना नासमझी और प्रेम के अंधेपन का परिणाम है। प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन माता-पिता से बढ़कर कोई नहीं होता।

नीट पेपर लीक पर कहा- देशहित में जो हो, वही होना चाहिए

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से नीट पेपर लीक के मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस विषय पर वे पहले भी अपनी बात रख चुके हैं। उन्होंने कहा, देश में जो भी हो, वह सबके हित में होना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन और राजनीति से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, राजनीति हमारा विषय नहीं है, धर्मनीति हमारा विषय है। हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान पर हमसे कुछ भी पूछिए, हम उस पर अपनी बात रखेंगे लेकिन राजनीतिक विवादों पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते।

ट्विशा शर्मा केस: गिरिबाला सिंह और समर्थ का जेल से बाहर आना मुश्किल, 14 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

भोपाल (नप्र)। ट्विशा शर्मा केस मामले में स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई है। गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को अभी जेल से बाहर आना मुश्किल लग रहा है। कोर्ट ने 14 जुलाई तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। दोनों आरोपियों को भोपाल सेंट्रल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था।

न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद दिया यह आदेश- कोर्ट ने यह आदेश उनकी पिछली न्यायिक रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद दिया है। सुनवाई के बाद दोनों की अगली सुनवाई की तारीख तक न्यायिक हिरासत में रखने का निर्देश दिया गया है। इस मामले की जांच कर रही सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने आरोपियों से और पूछताछ के लिए कस्टडी की मांग नहीं की है।

सीबीआई कर रही है जांच- एजेंसी दस्तावेजी, फोरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जांच करने के साथ-साथ मामले से जुड़े गवाहों के बयान दर्ज करके अपनी जांच जारी रखे हुए है। ट्विशा शर्मा 12 मई को अपने ससुराल में मृत पाई गई थी। इस घटना ने लोगों का ध्यान खींचा और उनके परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग की थी।

हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी थी जांच- इस बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद जांच सीबीआई को सौंप दी थी। तब से केंद्रीय एजेंसी मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है, जिसमें ट्विशा की मौत की वजह बने हालात भी शामिल हैं।

पूछताछ के बाद किया था गिरफ्तार

गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में, सीबीआई ने मामले के सिलसिले में पूछताछ के बाद ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह और उनके पति समर्थ सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था। शुरू में एजेंसी को पूछताछ के लिए कस्टडी रिमांड दी थी। सीबीआई की रिमांड पूरी होने के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तब से दोनों भोपाल सेंट्रल जेल में बंद हैं।

जांच चल रही है

सुनवाई के दौरान कोर्ट में सीबीआई ने यही कहा है कि जांच चल रही है। जांच के दौरान मिले सबूतों को सीबीआई ने उजागर नहीं किया है। वहीं, जब से मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है, यह केस कोर्ट की निगरानी में है। एजेंसी ने कई लोगों से पूछताछ की है।

पीएम सूर्य घर योजना में

तीन किलोवॉट के सौर संयंत्र लगाने पर मिल रही 78 हजार रूपये की सब्सिडी : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल (नप्र)। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि पीएम सूर्यघर योजना के तहत अब तक कुल एक लाख 43 हजार 150 उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। इनके बैंक खातों में 1010 करोड़ 25 लाख रूपये की सब्सिडी जमा कराई जा चुकी है। योजना के तहत एक किलोवॉट सोलर संयंत्र लगाने पर 30 हजार रूपये, दो किलोवॉट सोलर संयंत्र लगाने पर 60 हजार रुपए तथा तीन किलोवॉट या उससे अधिक के सोलर संयंत्र स्थापना पर 78 हजार रुपए की सब्सिडी केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही है।

कहां करें आवेदन

पीएम सूर्यघर योजना का शुभारंभ 13 फरवरी 2024 को हुआ था। योजना में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिसके लिए पीएम सूर्य घर योजना की वेबसाइट pmsuryaghar.gov.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए संबंधित विद्युत वितरण कंपनी की वेबसाइट अथवा उपाय एप, वॉट्सऐप चेटबॉट एवं टोल फ्री नं, 1912 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

उपभोक्ताओं को समय पर सब्सिडी मिले इसके लिए वेंडर और उपभोक्ता दोनों को ध्यान रखना होगा कि उनके बैंक खाते में नाम, आधार कार्ड में नाम तथा बिजली बिल में नाम एक समान होना चाहिए। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उपरांत विद्युत वितरण कंपनी में रजिस्टर्ड अधिकृत वेंडर से ही सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत सौर संयंत्रों में केवल स्मार्ट मीटर ही लगाए जा रहे हैं।

कंपनीवार स्थिति

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी क्षेत्र में 51 हजार 343 सोलर संयंत्रों पर 361 करोड़ 99 लाख, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी क्षेत्र में 58 हजार 715 संयंत्रों पर 4162 करोड़ 30 लाख 39 हजार और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी क्षेत्र में 33 हजार 092 सोलर संयंत्रों पर 231 करोड़ 95 लाख 50 हजार रूपये की सब्सिडी दी गई है।

जब बड़वानी के ग्रामीणों ने उठा लिए गैंती-फावड़े

सरकार सोई तो खुद ही बना डाली 7 किलोमीटर की सड़क

बड़वानी(नप्र)। विकास की राह जब सरकारी फाइलों में अटक जाए, तो मजबूरी लोगों को खुद रास्ता बनाने पर मजबूर कर देती है। बड़वानी जिले के दूरस्थ पाटी विकासखंड के महाराष्ट्र सीमा से लगे सागमाल गांव में ऐसा ही दृश्य देखने को मिल रहा है। वर्षों से पक्की सड़क की मांग पूरी नहीं होने पर ग्रामीण अब कुदाल, फावड़े और गैंती लेकर स्वयं करीब सात किलोमीटर कच्चे रास्ते की मरम्मत में जुट गए हैं। इसके लिए वे अपनी जेब से भी खर्च कर रहे हैं, ताकि जोरदार बारिश शुरू होने से पहले गांव का संपर्क पूरी तरह न टूटे।

पीपरकुंड ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले सागमाल तक झारड़ गांव के बाद आज तक पक्की सड़क नहीं बन सकी। ग्रामीणों का कहना है कि हर चुनाव में सड़क का वादा किया गया, लेकिन हकीकत आज भी वैसी ही है।

न खाद-बीज मिल रहा, न बाजार तक पहुंच रही फसल- गांव के मुन्ना नारगावे ने बताया कि सड़क खराब होने से किसानों को बीज, खाद और अन्य कृषि सामग्री लाने में भारी परेशानी होती है। फसल बाजार तक पहुंचाना भी मुश्किल होता है। दोपहिया और ट्रैक्टर चलाना जोखिम भरा है। इसी कारण ग्रामीणों ने स्वयं रास्ता सुधारने का निर्णय लिया।

ग्रामीण चेंदा ने बताया कि सबसे अधिक परेशानी बीमार लोगों को होती है। एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए मरीजों को करीब सात किलोमीटर तक झोली या अस्थायी पालने में उठाकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। कई बार हालात इतने गंभीर हो जाते हैं कि सड़क व इलाज के अभाव में लोग झाड़-फूंक करने वालों का सहारा लेने को मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि कई गर्भवती महिलाओं की रास्ते में ही प्रसूति हो चुकी है।

ग्रामीण सांचा और साय सिंह ने कहा कि उन्होंने विधायक, जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री तक को कई बार ज्ञापन दिए, लेकिन सड़क निर्माण की मांग अब तक अधूरी है।

बनने से बेहतर होगी कनेक्टिविटी- ग्रामीणों का मानना है कि यदि झारड़ से सागमाल तक सड़क बन जाती है तो न केवल गांव की जिंदगी आसान होगी, बल्कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बेहतर कनेक्टिविटी भी स्थापित होगी। इससे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध पर्यटन एवं धार्मिक स्थल तोरणमाल तक पहुंच भी सुगम हो जाएगी।

कलेक्टर ने दिए जांच के निर्देश- वहीं बड़वानी कलेक्टर जयति सिंह ने कहा कि सड़क निर्माण को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-4 के तहत आगे बढ़ाने के लिए अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। साथ ही, ग्रामीणों द्वारा किए जा रहे श्रमदान में ग्राम पंचायत की संभावित भूमिका और सहयोग की भी समीक्षा की जाएगी।

गूगल मैप के इस्तेमाल से आफत

गूगल मैप का उपयोग कर प्रसिद्ध धार्मिक व पर्यटन स्थल तोरण माल जा रहे बोकराटा गांव के तुकाराम पवार ने बताया कि बोकराटा से तोरणमाल की दूरी करीब 30 किलोमीटर है, लेकिन लगभग 10 किलोमीटर का रास्ता बेहद पथरीला और खतरनाक है। वहीं पीपरकुंड के बाबूलाल ने बताया कि महाशिवरात्रि मेले में हजारों श्रद्धालु तोरणमाल पहुंचते हैं और मानसून में बड़ी संख्या में पर्यटक यहां की प्राकृतिक सुंदरता देखने आते हैं। सड़क बनने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

कांग्रेस विधायक राजन मंडलोई ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र सीमा से लगे गांवों की सड़क का मुद्दा कई बार विधानसभा में उठाया है। झारड़-सागमाल सड़क बनने से स्थानीय लोगों के साथ-साथ तोरणमाल जाने वाले यात्रियों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी सर्वे में इस सड़क को शामिल कर बजट स्वीकृत किया जाएगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वे विधानसभा में यह मुद्दा लगातार उठाते रहेंगे।

इमामबाड़े के नाम पर महिला ने किया कब्जा

विरोध करने पर कॉलोनी के पुरुषों पर मामला दर्ज करवाया कार्रवाई की मांग लेकर महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंचीं

भोपाल (नप्र)। भोपाल के करोंद स्थित गैस राहत क्वार्टर की महिलाओं ने कॉलोनी की एक महिला पर इमामबाड़े के नाम पर कॉलोनी की सार्वजनिक जगह पर कब्जा करने का आरोप लगाया है।

महिलाओं का आरोप है कि आरोपी महिला विरोध करने पर कॉलोनी के पुरुषों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराती है। गाली-गलौज व मारपीट करती है। महिलाओं ने कहा कि हमने कई जगह शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए शिकायत करने कलेक्ट्रेट आए हैं। महिलाओं ने बताया कि हम किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं। ताजिया बनाने की परमिशन 10 दिन की रहती है, लेकिन यहां तो हमेशा के लिए इमामबाड़ा बना दिया गया। पहले यहां बच्चे खेलते थे, गाड़ियां खड़ी होती थीं, अब रास्ता ही बंद हो गया है। ये महिला इस जगह पर अवैध कब्जा करके उसे अपने व्यक्तिगत काम के लिए इस्तेमाल कर रही है।

धार्मिक स्थल के नाम पर बीच रास्ते में कब्जा कर लिया- महिलाओं ने आरोप लगाया कि कॉलोनी के बीच सार्वजनिक जगह और रास्ते पर शेड बनाकर कब्जा कर लिया गया है। उनका कहना है कि पहले यहां बच्चे खेलते थे और लोग आसानी से निकलते थे, लेकिन अब रास्ता बाधित हो गया है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि बिना वैध अनुमति स्थायी निर्माण कर लिया गया।

महिलाओं ने कहा कि जो भी अतिक्रमण का विरोध करता है, उसके साथ अभद्रता, गाली-गलौज और मारपीट की जाती है। विरोध करने वालों के खिलाफ थाने में झूठी शिकायतें और मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। महिलाओं का दावा है कि एक दर्जन से ज्यादा लोग ऐसे मामलों का सामना कर रहे हैं।

एक महिला ने कहा मेरी सात साल की बच्ची को ईंट मार दी थी। मैंने थाना निशातपुरा में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे घर के सामने भी कब्जा कर लिया। पिलर पर शेड लगा दिया है। हम विरोध करते हैं तो गाली देते हैं।

संपादकीय

सर्वोच्च कौन, सरकार या धार्मिक संस्था?

नमाज पढ़ने गए, रोजे गले पड़ गए। पंजाब में आप की भगवंत मान सरकार की हालत वैसी ही गई है। सरकार खुद को सबसे बड़ा सिख हितैषी साबित करने जा रही थी, लेकिन सिखों की सबसे बड़ी संस्था अकाल तख्त ने उसकी लगाम यह कहकर खींच दी कि सिखों के धार्मिक मामलों में कानून बनाने का अधिकार सरकार को किसने दिया। इस बारे में मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि सरकार ने यह कदम सिख संगत के कहने पर ही उठाया है। जिस तरह समूची सरकार अकाल तख्त में 5 सिंह साहिबानों के सामने पेश हुई, उससे यही संदेश गया कि मान सरकार ने संविधान में उल्लेखित पंथ निरपेक्षता से समझौता कर लिया है। जो हुआ है, वह लोकतंत्र की दृष्टि से ठीक नहीं है। यही नहीं अकाल तख्त श्री गुरू ग्रंथ साहिब की बेअदबी कानून मामले में सरकार को संशोधन करने का अल्टीमेटम देते हुए एक माह की मोहलत दी है। गौरतलब है कि पंजाब की मान सरकार ने पिछले दिनों श्री गुरू ग्रंथ साहिब बेअदबी मामले में सख्त कानून बनाने के इरादे से ' जगत जोत श्री गुरू ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक 2026 पारित कराया। इसके तहत पवित्र ग्रंथ की बेअदबी करने वाले को उम्र कैद और 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान था। इस कानून के पारित होने पर अकाल तख्त ने इस पर गहरी नाराजी यह कहकर जताई कि उससे बिना सलाह लिए सरकार ने यह कानून कैसे पारित करा दिया। क्योंकि यह सिख धर्म से जुड़ा मसला है। अकाल तख्त को विधेयक और भी कुछ बातों पर आपत्ति थी। इस नाराजी के बाद अकाल तख्त के सम्मुख सफाई देने सत्तारूढ़ आप समेत सभी दलों के सिख विधायक सफाई देने पहुंचे। सुनवाई के दौरान अकाल तख्त जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने कानून पर 6 एतराज जताए। उन्होंने कहा कि सरकार बेअदबी करने वालों को सजा देने के लिए कानून बनाए, इस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन सिख शब्दावली, मर्यादा और पंथ से जुडेव मामलों में विधानसभा फैसला नहीं कर सकती। तब तक इस कानून को होल्ड किया जाए। जत्थेदार ने 2 सवाल पूछे। इस दौरान विधायकों ने माना कि कानून को बिना पढ़े सहमति दी सुनवाई से पहले जत्थेदार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के दो वीडियो भी सुनवाए। पेशी के लिए आप के सभी सिख मंत्री और विधायक नंगे पैर लिखित स्पष्टीकरण के साथ अकाल तख्त पहुंचे थे। कांग्रेस, अकाली दल और निर्दलीय विधायक भी सुनवाई में मौजूद रहे। जत्थेदार कुलदीप सिंह ने कहा कि सरकार सिखों के लिए कोई कानून बनाए तो उसे सिखों की राय लेनी चाहिए। इस पर आप विधायक इंद्रवीर निज्जर ने कहा कि जब सुझाव मांगे थे तब एसजीपीसी को बुलाया था। निज्जर ने कहा कि कमेटी की तरफ से कोई चिट्ठी नहीं भेजी गई। सरकार का मुझे नहीं पता। कांग्रेस विधायक प्रताप बाजवा ने कहा कि मैंने इस बारे में सदन में मांग उठाई थी। स्पीकर ने नहीं मानी। इस पर आप विधायक जगरूप सिंह ने कहा कि हमने कानून को सहमति दी। लेकिन पढ़ा नहीं। अकाल तख्त ने सिख शब्दावली को बदलने पर भी कड़ा ऐतराज किया। उसने कहा कि विधानसभा को सिख शब्दावली तय करने का हक नहीं है। बीड़ के साथ स्वरूप कहते तो कोई ऐतराज नहीं। यही नहीं, कानून बनाने से पहले सरकार ने सिख धार्मिक संस्थाओं और अकाल तख्त से औपचारिक सलाह नहीं ली। जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने यह भी कहा कि सरकार ने अकाल तख्त के पहले दिए गए निर्देशों की अनदेखी की। धार्मिक मामलों में अकाल तख्त की सर्वोच्चता निर्विवाद है, लेकिन क्या किसी चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को किसी शीर्ष धार्मिक संस्था के आगे पेश होना चाहिए, यह बड़ा सवाल है।

नजरिया

अरुण कुमार त्रिपाठी

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

भगवान के भरोसे है भारत की नागरिकता

भारतीय नागरिकता पर विदेश मंत्रालय के बयान के बाद देश में एक नए किस्म का भ्रम पैदा हो गया है। अब पासपोर्ट धारी लोग भी एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि जिस दस्तावेज के आधार पर हम विदेश में भारतीय नागरिक समझे जाते हैं क्या वह दस्तावेज महज यात्रा करने की एक परमिट है? चूंकि मौजूदा सरकार और सत्तारूढ़ दल के लोग यह बात बार बार कहा करते हैं कि विदेशी नागरिकों के घुसपैठ का मुद्दा किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है बल्कि वह राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है इसलिए यह भ्रम अल्पसंख्यक समाज के साथ हिंदू समाज के मध्यवर्ग और दूसरे वर्गों में भी व्याप्त हो रहा है कि जब सरकार नागरिकता साबित करने के लिए प्रमाणपत्र मांगेगी तो उन्हें कौन कौन सा कागज (दस्तावेज) पेश करना पड़ेगा। और उसके लिए नोटबंदी, कोरोना और एसआईआर की तरह कितना हाहाकार मचेगा। भ्रम की इस स्थिति में एक लतीफा याद आता है। एक राजा ने अपने एक कारिंदे को जंगल में ऊंट चराने के लिए भेजा। उस व्यक्ति ने ऊंटों की नकेल और उन्हें बांधने वाली रस्सियां खोल दीं ताकि वे आराम से जंगल में चर सकें और उन सबको लेकर एक पेड़ की छाया में आराम करने लगा। राज्य कर्मचारी को नींद आ गई और शासकीय सेवा के ऊंटों ने अपने को एकदम मुक्त समझ लिया। जब कर्मचारी की नींद खुली तो उसने देखा कि ऊंट कहीं है ही नहीं। बहुत ढूंढा लेकिन वे दिखे नहीं। शासकीय भय के मारे वह बदहवास हो गया। थोड़ी देर बाद जंगल के मार्ग से एक और शासकीय कर्मचारी गुजरते हुए दिखा, ऊंट वाले ने उसे नकेल और रस्सियां सौंपते हुए कहा कि 'जाकर कह देना उनसे जिनके थे वे, पता नहीं कहां गए जिनके हैं ये'। ऐसा ही एक प्रसंग गैबरियल गार्सिया मार्खेज के उपन्यास 'वन हन्ड्रेड ईयर आफ सालिट्यूड' में भी आता है। अचानक पूरे गांव की स्मृति चली जाती है और वे एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाते। स्मृति लौटने तक पूरे गांव में तमाम तरह के नाटक होते हैं जिसमें हास्य, करुणा और त्रासदी सभी किस्म के भाव उभरते हैं। मार्खेज ने उसका बड़ा रोचक वर्णन किया है।

लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि जब पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, मतदाता परिचय पत्र नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है (जिस पर नाम नहीं लिखा होता), हाई स्कूल का सर्टीफिकेट नहीं है तो आखिर कौन सा दस्तावेज भारतीय नागरिकता का प्रमाण है। दरअसल नागरिकता की राजनीति करने वाली पार्टी को भ्रम पैदा करना, लोगों में भय पैदा करना और फिर अहसान करते हुए कोई कागज सौंपना एक परपीड़क किस्म का सुख देता है और राजनीतिक लाभ पैदा करता है। इसलिए विदेश मंत्रालय के बयान से लग गया है कि आने वाले समय में भारत में नागरिकता के दस्तावेज को लेकर भारी उथल-पुथल मचने वाली है और लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर हैरान होने से कोई रोक नहीं सकता। हालांकि सिर्फ पासपोर्ट धारक को भारत का नागरिक मान लेने से भी देश की बड़ी आबादी को परेशानी होती। क्योंकि देश में सिर्फ 9.3 करोड़ से लेकर 10.5 करोड़ यानी 6.5 से 8.7 प्रतिशत लोगों के पास ही भारत का वैध पासपोर्ट है। पासपोर्ट यानी वह पुस्तिका जिस पर अशोक का चिह्न बना है और भारतीय गणराज्य लिखा है और जब भी आप विदेश दौरा करते हैं तो उस पर वीसा का कागज चिपकाया जाता है और आव्रजन की मुहर लगती है। जिसे आप विदेशों में शान से दर्शाते भी हैं।

भारत जैसे प्राचीन देश की नागरिकता कागज पर आधारित होनी नहीं चाहिए बल्कि जन्म के आधार पर स्वाभाविक होनी चाहिए यह बात हमारे संविधान निर्माताओं ने समझ ली थी। हालांकि विभाजन जैसी महात्रासदी के चलते उन्हें इसे निर्धारित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। संविधान की मसविदा समिति के अध्यक्ष डॉ भीमराव आंबेडकर ने कहा था कि नागरिकता वाले प्रावधानों ने समिति को काफी सिरदर्दी दी। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता पर चर्चा की गई है और उसे परिभाषित किया गया। उसी के साथ नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया और उसमें नागरिकता के मामले में देश में रह रहे मनुष्यों की स्थिति और सरकार के प्रपत्रों के अर्थ को स्पष्ट किया गया। जन्मजात नागरिकता के बारे में यह कानून कहता है कि जिन लोगों का जन्म 1950 और 1987 के बीच भारत में हुआ वे भारत के नागरिक हैं। जिनका जन्म 1987 से 2003 के बीच हुआ उन्हें नागरिकता तब मिलेगी जब उनके माता पिता में से कोई भी जन्म के समय भारतीय नागरिक रहा हो। अगर किसी का जन्म भारत के बाहर होता है लेकिन उसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारतीय नागरिक है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी लेकिन इसके लिए जन्म के एक साल के भीतर उसे भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीयन कराना होगा। इसके अलावा भारत में लंबे समय तक लगातार रहने वाले अनिवासी विदेशी नागरिक को भी नागरिकता देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार को पास किसी विशिष्ट व्यक्ति को नागरिकता देने का विशेष अधिकार है। दलाई लामा और अदनान सामी जैसे लोगों को इसी प्रावधान के तहत नागरिकता दी गई है। बिहार में एसआईआर के दौरान दिखाए जाने वाले 11 दस्तावेजों की सूची पर जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो फैसले में कहा गया कि इन दस्तावेजों में पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र के अलावा कोई भी दस्तावेज नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है। नागरिकता का सवाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 1960 से पेश आ रहा है। अब्दुल खादिर के मामले में अदालत ने उसे विदेशी नागरिक मानने से इंकार कर दिया जबकि उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था। लेकिन 1962 में इजहार खान के मामले में पाकिस्तानी पासपोर्ट धारक को पाकिस्तानी नागरिक माना गया। भारत विभाजन के बाद जैसे जैसे भारत और पाकिस्तान के करीब आने और फिर से एक होने की संभावना समाप्त होने लगी वैसे वैसे नागरिकता की परिभाषा भी संकीर्ण होती गई। अस्सी के दशक में उठे असम आंदोलन ने नागरिकता की परिभाषा को और कठोर व संकीर्ण बनाने की ओर प्रेरित किया। 1955 का नागरिकता अधिनियम उन सभी को भारतीय नागरिक मानता था जो भारत में रह रहे हैं या जिनका जन्म इस धरती पर हुआ है। लेकिन पड़ोसी देशों से लगातार होने वाले युद्धों और देश के भीतर खदबदाती सांप्रदायिक राजनीति ने नागरिकता अधिनियम में छह बार संशोधन करवाया। इनमें 1986, 2003 और 2019 के संशोधन गहरा असर डालने वाले हैं। 2005 में सर्वानंद सोनोवाल के एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई अपने को किसी देश का नागरिक बताता है तो नागरिकता साबित करने का दायित्व उसी पर आता है।

नागरिकता पर सबसे अधिक विवाद तो 2019 के सीएए एनआरसी ने पैदा किया और उस पर हुए आंदोलन ने उन कानूनों की अधिसूचना को लंबे समय तक रोक कर रखा। नागरिकता पर सरकार की ओर से पैदा किए गए भयानक भ्रम की इस स्थिति ने उदारता और समावेशिता पर आधारित भारतीय स्वाधीनता आंदोलन और प्राचीन संस्कृति के विराट दर्शन को संकीर्ण राष्ट्रवाद के दरवाजे पर लाकर पटक दिया है। इसके राजनीतिक नफा नुकसान तो अपनी जगह हैं लेकिन आज पूरा देश आशंका और आत्मसंदेह के वातावरण में जीने को अभिशप्त है। कभी गांधी जी ने कहा था कि अगर समस्त भारतीय धर्मग्रंथ नष्ट हो जाएं और बृहदारण्यक उपनिषद की एक पंक्ति बचे जो कहती है -सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यंति मा कश्चिद् दुःख भा भवेत, तो हमारा काम चल जाएगा। विश्व नागरिकता की बात करने वाले डॉ राम मनोहर लोहिया तो पासपोर्ट और बीसा दोनों का विरोध करते थे। इसीलिए उनके 'मैनकाइंड' के संपादकीय बोर्ड के श्रीलंकाई सदस्य किसी भी देश में बिना बीसा पासपोर्ट के घुस जाते थे और फिर निष्कासित किए जाते थे। कागज की मांग जितना किसी देश को जितना पारदर्शिता और वैधानिकता की ओर ले जाती है उतना ही अपने सामान्य नागरिकों के लिए परेशानी पैदा करती है। कभी बस्तर के कलेक्टर रहे और अनुसूचित जाति और जनजाति के आयुक्त डॉ ब्रह्मदेव शर्मा लेखपालों से परेशान आदिवासियों से कहते थे कि जब कोई कागज मांगे या दिखाए तो कह दो कि कागज तुम अपने पास रखो और जमीन तो हमारी है। यानी कागज तुम्हारा जमीन हमारी। दरअसल यही कागज दिखाकर देश की आदिवासी और मूल निवासियों की बड़ी आबादी को विस्थापित किया गया है और उनके जल जंगल और जमीन को छीना गया है।

आज पासपोर्ट, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, जाति प्रमाण पत्र, डिग्री या हाई स्कूल का सर्टीफिकेट कोई दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है और सरकार ने न तो नागरिकता का कोई कागज जारी किया है और न ही बताया है कि कौन सा कागज इसका अंतिम प्रमाण होगा। ऐसी ही भ्रामक स्थिति के बारे में अमेरिकी राजनीतिशास्त्री मायन वीनर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तकें 'पॉलिटिक्स आफ स्कैरिसिटी' और 'द इंडियन पैराडाक्स' में कहा है कि इतने अंतरविरोधों और अभावों के बावजूद अगर यह देश चल रहा है तो सरकारों के भरोसे नहीं बल्कि भगवान के भरोसे। ऐसे में चाहे अयोध्या के राम मंदिर की लूट हो, मध्य प्रदेश या राजस्थान का भ्रष्टाचार हो या भारतीय जनता की नागरिकता का सवाल हो भारत के लोग अब यही सोच कर बैठे है कि इन सबका न्याय भगवान राम ही करेंगे।

विश्व राजनीति

डॉ. सुधीर सक्सेना

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

वैश्विक - परिदृश्य में उभरता कतर

कुछ तो बेपनाह दौलत, कुछ कुशल राजनय और कुछ छवि-अभिसारी उपक्रम कि मध्यपूर्व का छोटा सा देश क़तर वैश्विक -परिदृश्य में तेजी से उभर आया है। फीफा की मेजबानी और फीफा में शिरकत, दुनिया में काबिले-तारीफ जीडीपी, लंदन में सर्वाधिक संपत्ति की खरीदी और कलाकृतियों के बेहतरीन म्यूजियम की स्थापना तथा अमेरिका-ईरान जंग में मध्यस्थता में सफलता क़तर को लगातार सुर्खियां बख्श रही हैं। बिला शक आगामी समय में इसमें और इजाफा होने के आसार हैं।

मुमकिन है कि आप क़तर को नहीं जानते हों। मुमकिन है कि आपने उसकी राजधानी दोहा का नाम नहीं सुना हो और यह भी मुमकिन है कि अपने शेख तमीम बिन हमद अल थानी का नाम भी नहीं सुना हो, लेकिन अपनी धुरी पर घूमती दुनिया बदल रही है। शीतयुद्ध के बाद एक ध्रुवीय दुनिया में नये-गुल खिल रहे हैं। यह अमेरिका के निर्लज्ज नव उपनिवेशवाद का दौर है, अलबत्ता मस्क्वा-बीजिंग-तेहरान की धुरी तेजी से उभर रही है और मध्यपूर्व में जियो-पॉलीटिकल समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। इन्हीं सन्दर्भों में क़तर की अहमियत भी बढ़ गयी है।

क़तर अरब प्रायद्वीप के उत्तर-पूर्वी तट पर क्षेत्रीय प्रायद्वीपीय देश है। दक्षिण में सऊदी अरब और तीन ओर से फारस की खाड़ी से घिरा क़तर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का क्रमशः दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा भंडार है। सन् 1783 में अल खलीफ वंश के राज के बाद यहां पहले तुर्की और फिर ब्रिटेन का शासन रहा। सन् 1971 में आजादी के बाद इसके दिन बहुरे और इसने भौतिक प्रगति की कुलांचे भरीं।

क़तर को जानने के लिये यहां के शासक अमीर शेब तमीम बिन हमद अल थानी के रसूख को जानना जरूरी है। उनके लिये जून, 13 में उन शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने सत्ता छोड़ दी थी, जिन्होंने वसन्त क्रांति में सीरिया और लीबिया जैसे देशों में बागियों का समर्थन किया था। आज अमीर की निजी संपत्ति 2.4 बिलियन डॉलर कूती जा रही है। उनकी खेलों और खेल स्पर्धाओं में रूचि है। वह खुद बैडमिंटन खेलते हैं। सन् 1998 में कतरी सेना में सेकेंड लेफ्टिलेंट के बाद वह सन् 2009 में डिप्टी कमांडर इन चीफ हो गये। वह अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के मेंबर हैं। उनके पास सेंट जर्मेन नामक फ्रेंच फुटबॉल क्लब का स्वामित्व है। उन्होंने तीन शादियां कीं। पहली सन् 2005 में अपनी चचेरी बहन शेखा जवाहर और फिर सन् 2009 में शेखा अनूद से और फिर शेखा नूर से। उनके 11 बेटे और 13 बेटियां हैं। उन्होंने इंग्लैंड के शेरबॉर्न स्कूल और फिर वहीं की रायल मिलिट्री एकेडमी में पढ़ाई व ट्रेनिंग ली। यह उनका रसूख ही है कि शेरबार्न स्कूल की इंग्लैंड के बाहर एक ही शाखा है और वह भी क़तर की राजधानी दोहा में है।

क़तर की आबादी ज्यादा नहीं है। कुल जमा यही कोई चौंतीस लाख। करीब चालीस फीसद आबादी उस दोहा में रहती है, जो 19वीं सदी में शनैः शनैः विकसित हुआ। यहां तीन घेरों में योरोपीय और इस्लामी स्थापत्य की बस्तियां आबाद हैं। क़तर में चार लाख से अधिक हिन्दु रहते हैं। करीब 12 प्रतिशत हिन्दु मुख्यतः भारत व नेपाली मूल के हैं। क़तर की समृद्धि और वैभव में इनका बड़ा योगदान है। सौ कतरी रियाल करीब 2600 भारतीय रूपयों के बराबर हैं। क़तर की एक और खूबी है महिलाओं का कम अनुपात। लिंगानुपात में असमानता के चलते यहां महिलाओं की आबादी कुल सात लाख के आसपास है। बड़ी बात यह है कि यहां के अमीर लंदन में संपत्ति खरीदी में अव्वल हैं। वह लंदन में अब तक 35 से 40 बिलियन डॉलर का निवेश कर चुके हैं। अनुमान है कि आगामी चार-पांच साल में पांच बिलियन डॉलर तक का निवेश और होगा। क़तर दुनिया में अपनी जीडीपी के लिये जाना जाता है।

जीडीपी के मान से वह दुनिया में पांचवीं पायदान पर है, जबकि मोनाको सर्वोच्च पायदान पर।

क़तर अपने कला संग्रहालयों के लिये भी ख्यात है। क़तर म्यूजियम की स्थापना सन् 2005 में हुई थी। सन् 2008 में खुले म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट और सन् 2010 में स्थापित मतफ अरब म्यूजियम ऑफ माडर्न आर्ट्स दर्शनीय हैं। सन् 2022 में दोहा फोरम की संरक्षिका शेखा अल मयस्सा बिंत हमद बिन खलीफा अल थानी ने तीन अन्य म्यूजियमों का ऐलान किया, जो लासानी हैं। सन् 2010 में निर्मित कतरी कलाग्राम (आर्टविलेज) का नजारा मंत्रमुग्ध करता है। सन् 2018 से दोहा में नियमित कला महोत्सव हो रहा है। शेखा अल मयस्सा कतरियों में कला अभिरूचि जगाने और अवाम को कलाकृतियों से 'कनेक्ट' करने के उपक्रमों के लिये जानी जाती है। सार्वजनिक स्थलों विभिन्न कला माध्यमों की कृतियों का प्रदर्शन आम बात है। इस्लामी आर्ट म्यूजियम में विगत करीब चौदह सौ वर्षों की इस्लामी कला निधियां संकलित हैं। दोहा में हमद अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर टर्मिनल के मध्य में 23 फुट का पीताभ टेडी बियर बरबस ध्यान आकृष्ट करता है। अर्स फिशर निर्मित बीस टन वजनी यह कांस्य-कृति सन 2011 में न्यूयार्क में 6.8 मिलियन डॉलर की बोली लगाकर खरीदी गयी थी। बताते हैं कि क़तर प्रतिवर्ष एक बिलियन डॉलर की रकम कला पर खर्च करता है। यह रूझान इस छोटे से इस्लामी मुल्क को अलग रंगो-नूर से माड़ती है। इस कला संदर्भ का एक और अहम पहलू यह है कि बीते बरसों में कतरी युवतियों में कला-संकाय के प्रति अभिरूचि बढ़ी है और बड़ी संख्या में वे कला-उपक्रमों से जुड़ रही हैं। सन् 1986 में क़तर विश्वविद्यालय में कला विभाग की स्थापना से इसे गति मिली है और यथार्थवाद, अति यथार्थवाद, अमूर्तन, व्यंजनावाद और कैलीग्राफी को विस्तार।

जब प्रतिष्ठित कतरियों की बात होती है तो सन् 2007-13 में प्रधानमंत्री रहे शेख हमद बिन जासिम बिन जबेर अल थानी का भी जिक्र होता है, जो सबसे धनी कतरी हैं। 1.2 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ वह वैश्विक - निवेश और डयूश बैंक में 'स्टेक' के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान शासक 23 भाई बहने हैं। यूं भी अल थानी वंश यहां सेना, प्रशासन, कार्पोरेट और कारोबार में पैठ और दबदबे के लिए जाना जाता है। थानी कुल के सदस्यों की संख्या बीस हजार से ज्यादा है।

क़तर में कॉफी सर्वाधिक लोकप्रिय पेय है। इसे छोटी-छोटी प्यालियों में परोसा जाता है, जिसमें चीनी मिलाई जाती है, या फिर साथ में खजूर पेश किया जाता है। कड़क चाय में पिसी इलायची घोलते हैं और उसमें गाढ़ा दूध मिलाते हैं। क़तर के 2022 फीफा विश्व कप को प्रोत्साहन स्वरूप 282 मिनट की एक डाक्यूमेंट्री बनी थी। इसके लिये डेविड बेकहैम को 125 मिलियन पाउंड की रकम दी गयी थी। फीफा 26 के लिए क़तर ने सन् 25 में ही क्वालीफाई कर लिया था।

क़तर आज तकनीकी स्टार्ट अप में अग्रणी है। क़तर टॉवर्स को विलासिता का शिखर माना जाता है। ईरान-अमेरिका जंग में क़तर बार-बार सुर्खियों में आया। रास लाफान में एलएनजी संयंत्र पर हमले में भारतीयों समेत 13 मारे गये और 66 आहत। किंतु ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता में कामयाबी ने कतर को राजनय में ऊंची पायदान पर प्रतिष्ठित कर दिया। इतालवी पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने क़तर की भूमिका की मुक्त कंठ सराहना की। मध्यस्थता के खेल में पाकिस्तान उसके सहयोगी या जूनियर की भूमिका निभाता नजर आया। ईरान की नजर में यूं भी क़तर अधिक विश्वसनीय है। क़तर इधर तुर्किये और सऊदी अरब के भी नजदीक आया है और उसने मिस्र समेत अनेक देशों से तार जोड़े हैं। ईरान-अमेरिका संघ के मजमून की इबारतें लिखने में उसकी भूमिका पाकिस्तान से अधिक मायने रखती है। उसकी जियोपालीटिकल-हैसियत मध्यपूर्व में उसकी भूमिका के महत्वपूर्ण होने का आभास देती है।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

जवाहर चौधरी

लेखक व्यंग्यकार हैं।

सच जानलेवा और झूठ पैरासेटामाल

व्यावहारिकता कहती है कि 'कड़वा कड़वा थू मीठा-मीठा गप'। कितनी तो तकलीफें हैं आज के टैम में। कहीं पेपर लीक के बाद बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और कहीं कोचिंग सेंटर में जिंदा जल कर मर रहे हैं। कहीं मंगेतर-मार लड़कियाँ सुर्खियों में हैं तो कहीं भगवान के घर में चोर घुसे बैठे हैं!! बताओ इस सच से आंख मिलाना कितना कठिन है। जो लोग महंगाई और बेरोजगारी के सच से दोहरे हुए जा रहे हैं वे इस सच को कैसे बर्दाश्त करेंगे!! हर कोई कवि तो होता नहीं कि कुछ लिख लिखा कर अपना गुस्सा निकाल दे ! इन जानलेवा सच के बीच झूठ पैरासेटामाल है, दर्द कम करता है। जरा सोचिये जब आप पढ़ते हैं कि सरकार चिंतित है तो मन को कितनी तसल्ली होती है! लगता है कोई है हमारा अपना ।

लगातार झूठ पढ़ने सुनने की आदत हो जाए तो आदमी सच को संदेह से देखने लगता है। यह बात सुनते ही दयाराम टकले, जो इस समय सोलह पेजी अख़बार लिये बैठे थे, बोले - ' ऐसा नहीं है भाऊ, आज के मुश्किल टाइम में आदमी को जीना सीखना पड़ता है। सच रामजी के जमाने से कड़वा होता था, लेकिन आज का सच पहले से ज्यादा कड़वा है । व्यावहारिकता कहती है कि 'कड़वा कड़वा थू मीठा-मीठा गप'। कितनी तो तकलीफें हैं आज के टैम में। कहीं पेपर लीक के बाद बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और कहीं कोचिंग सेंटर में जिंदा जल कर मर रहे हैं। कहीं मंगेतर-मार लड़कियाँ सुर्खियों में हैं तो कहीं भगवान के घर में चोर घुसे बैठे हैं!! बताओ इस सच से आंख मिलाना कितना कठिन है। जो लोग महंगाई और बेरोजगारी के सच से दोहरे हुए जा रहे हैं वे इस सच को कैसे बर्दाश्त करेंगे!! हर कोई कवि तो होता नहीं कि कुछ लिख लिखा कर अपना गुस्सा निकाल दे! इन जानलेवा सच के बीच झूठ पैरासेटामाल है, दर्द कम करता है। जरा सोचिये जब आप पढ़ते हैं कि सरकार चिंतित है तो मन को कितनी तसल्ली होती है! लगता है कोई है हमारा अपना। वे कहते हैं जाँच करवाएंगे, दोषियों को बक्षा नहीं जाएगा तो खौलते खून को फ़ट्ट-से स्टे मिल जाता है। समय रहते शीतल झूठ सामने आ जाए तो सच के फफोले कम दुखते हैं। उसके बाद हसे पंद्रह दिनों में नया कुछ हो जाता है और लोग पुराना भूल जाते हैं। हो गया काम, जय श्रीराम । ये रिवाज़ है लोकतंत्र का। और अपना ये जो मिडिया है ना... मरहम है, ये न हो तो जनता का हितैषी कौन है बताइये !! संवेदनशील लोग बेचारे सच की कढ़ाही में डीप फ्राई हो कर किस पार्टी में परोस दिये जाएं पता नहीं चलेगा। जब लोगों के कानों में 'भाइयो और बहनो ' शब्द पड़ते हैं तो कितना प्यारा लगता है! भले ही यह लोकप्रिय झूठ हो, पर सबको अच्छा लगता है। इसके बाद शब्दों का शेफ झूठ का बूफ़े लगा देता है और जनता स्वरुचि भोज का आनंद लेने लगती है। अगर चारों तरफ सच ही सच होता तो गरीब आदमी पहली समझ पैदा होते ही मर जाता।' रामजी टकले ने ब्रेक लेते हुए हमारी तरफ देखा।

हमें कुछ बोलना ही है, वरना उन्हें लगेगा हम ठूंठ हैं । कहा - आपकी बात ठीक है। लेकिन संसार में सब झूठ झूठ थोड़ी चलता है थोड़ा बहुत सच तो कहना ही है पड़ता है । जैसा कि अभी आपने कहा वह सब सच है।

'कड़वा था ना? लोकतंत्र में सवाल कड़वे-मीठे का है। राजनीति कड़वे सच को मीठे झूठ में बदल देने की कला है। जो खमखाह थे वे वतनपरस्त हो गए । मान न मान, मैं तो महान! अशिक्षित लोग पाठ पढ़ा रहे हैं, कभी पुलिस ढूंढा करती थी जिन्हें अब सुरक्षा दे रही है, सलाम भी ठोक रही है। उनकी आत्मा कड़वे घूंट पी पी कर मर गई बेचारी। व्यवस्था की इस मजबूरी को महसूस करके देखिये हैरान हो जाएंगे।' टकले दुखी हो गए।

'जागरूकता आएगी तब लोग समझेंगे।'

'कैसे समझेंगे!? आजकल कितने मैसेज, वीडियो और रीलें आ रही है फोन में! सब जानते हैं कि झूठ हैं, लेकिन दनादन फरवर्ड करने में मजा आता है । ये झूठ न हो तो विद्रोह हो सकता है । झूठ पैर से नहीं डाटा से चलता है अब। समझ के रास्तों पर पहरे हैं। .... अरे !! तुम तो चिंतित हो रहे हो !! लो , अखबार पढ़ लो , मजा आ जाएगा ।'

जल संवर्धन

प्रो. मनोज कुमार

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

अभियान से आगे हमारी जवाबदारी का समय

जल प्रकृति का अमूल्य उपहार है और पृथ्वी पर जीवन का आधार भी। मानव, पशु-पक्षी, वनस्पति तथा समस्त जीव-जगत का अस्तित्व जल पर निर्भर है। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में जल को जीवन, पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। किंतु बढ़ती जनसंख्या, अनियोजित शहरीकरण, औद्योगीकरण, जल स्रोतों का अंधाधुंध दोहन तथा जल प्रदूषण के कारण आज विश्व गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। अनेक क्षेत्रों में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है और नदियाँ, तालाब तथा झीलें सूखती जा रही हैं। यदि समय रहते जल संरक्षण के प्रभावी उपाय नहीं अपनाए गए, तो भविष्य में पीने योग्य जल की भारी कमी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक का नैतिक और सामाजिक दायित्व है।

मानसून आँख-मिचौली कर रहा है। लगता है कि बादल अब बरस पड़ेंगे की तब बरस पड़ेंगे लेकिन खेतों से लेकर शहरों तक की आँखें पथराई जा रही है। बादल बिना बरसे चले जा रहे हैं। यह समस्या साल-दर-साल बढ़ती चली जा रही है। अंधाधुँध विकास के कारण हमने ही यह स्थिति उत्पन्न की है। बीते सालों के मुकाबले इस साल गर्मी का ताप अधिक रहा और आने वाले सालों की कल्पना करना भी मुश्किल है। ऐसे में जरूरी है कि बीते दिनों को हम लौटा नहीं सकते लेकिन आने वाले दिनों को सुधार जरूर सकते हैं। राज्य में डॉ. मोहन सरकार ने जल गंगा संवर्धन अभियान का आरंभ प्रतिपदा (गुड़ी पड़वा) से शुरू किया था जो माह जून के आखिरी दिन थम गया। यह अभियान समाज को जागृत करने तथा नदियों, तालाबों, कुँओं और बावडियों जैसे जल स्रोतों का पुनरुद्धार और संरक्षण करना प्रमुख था। स्वाभाविक है कि सरकार अपना काम कर रही है लेकिन समाज की हिस्सेदारी भी जरूरी है। सरकारी आंकड़ों को मानें तो यह अभियान ने सार्थकता प्रदान की है और मान लेना चाहिए कि आंकड़े हवा में जारी नहीं किए जाते हैं। लेकिन इससे आगे की बात यह है कि सरकार के इस अभियान में जिन जलस्रोतों को पुर्नजीवन दिया गया, उसे बचाने और संवारने का समय अब आ चुका है।

जल प्रकृति का अमूल्य उपहार है और पृथ्वी पर जीवन का आधार भी। मानव, पशु-पक्षी, वनस्पति तथा समस्त जीव-जगत का अस्तित्व जल पर निर्भर है। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में जल को जीवन, पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। किंतु बढ़ती जनसंख्या, अनियोजित शहरीकरण, औद्योगीकरण, जल स्रोतों का अंधाधुंध दोहन तथा जल प्रदूषण के कारण आज विश्व गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। अनेक क्षेत्रों में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है और नदियाँ, तालाब तथा झीलें सूखती जा रही हैं। यदि समय रहते जल संरक्षण के प्रभावी उपाय नहीं अपनाए गए, तो भविष्य में पीने योग्य जल की भारी कमी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक का नैतिक और सामाजिक दायित्व है।

इस स्थिति में हमें जल गंगा संवर्धन अभियान के आगे अब चलने की जरूरत है। यह अभियान गर्मी के मौसम में शुरू हुआ और जल स्रोतों को स्वच्छ और साफ किया गया। अब इन जल स्रोतों को लबालब करने का समय आ गया है। मानूसन अभी भले ही हमसे आँख-मिचौली कर रहा है लेकिन जब बरसेगा तो हमें लबालब कर देगा, यह उम्मीद बेमानी नहीं है। ऐसे में हम सबका दायित्व बन जाता है कि बारिश की इन बूँदों को सहेज और संवार कर रखें। जल संरक्षण के अनेक उपाय बताये जाते हैं और आप हम में से अनेक लोग करते हैं और यही जल गंगा संवर्धन अभियान को सार्थकता प्रदान करेगा।

जल संरक्षण के लिए सरकार तो जो करती है और करेगी, हम व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर क्या कर सकते हैं, इस पर विचार और पहल करने की जरूरत है। सबसे पहले वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना चाहिए। घरों, विद्यालयों, कार्यालयों तथा सार्वजनिक भवनों में वर्षा के जल को एकत्र कर भूजल पुनर्भरण किया जा सकता है। इससे भूजल स्तर में सुधार होता है और भविष्य के लिए जल उपलब्ध रहता है। इसी तरह वृक्षारोपण भी जल संरक्षण का महत्वपूर्ण माध्यम है। पेड़ वर्षा को आकर्षित करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं तथा भूजल पुनर्भरण में सहायता करते हैं। इसलिए अधिक से अधिक पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना आवश्यक है। कुछ साथी इस दिशा में सक्रियता के साथ प्रयास कर रहे हैं और बारिश के पहले ही लोगों को अपने घरों और मोहल्ले में पौधे लगाने की सलाह दे रहे हैं। वर्षाकाल में पौध रोपण करने से इसका परिणाम सुखदायक होता है और थोड़े समय में यह पौध वृक्ष का स्वरूप ग्रहण कर लेता है।

खेती किसानी करने वाले किसान भाईयों को भी कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों, जैसे ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे कम जल में अधिक सिंचाई संभव होती है और जल की बचत होती है। किसानों को कम पानी वाली फसलों को अपनाने तथा वैज्ञानिक खेती के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। खेती के लिए पानी की जरूरत सबसे अधिक होती है और खेती ना हो पायी तो अनेक प्रकार के संकटों से समाज को जूझना पड़ सकता है।

यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। आवश्यक है कि नल को अनावश्यक खुला न छोडऩा, रिसाव की तुरंत मरम्मत कराना, आवश्यकता के अनुसार ही जल का उपयोग करना तथा पानी की बर्बादी रोकना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। छोटी-छोटी सावधानियाँ प्रतिदिन हजारों लीटर जल बचा सकती हैं। हमें इस मानसिकता से बाहर आना होगा कि हर कार्य सरकार को करना चाहिए। यह ठीक है कि संसाधन जुटाने और समाज को जागरूक करने का कार्य सरकार करती है लेकिन इसे परिणाममूलक बनाने की जवाबदारी अंततः समाज की होती है। गंगा जल संवर्धन अभियान के माध्यम से जलस्रोतों को पुर्नजीवित करने का कार्य सरकार ने कर दिया है लेकिन इनके लंबे और सुदीर्घ जीवन के लिए जल संरक्षण का कार्य हमें करना होगा। जल संरक्षण एक सामूहिक अभियान है, जिसमें समाज की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। प्रत्येक व्यक्ति को जल का महत्व समझना चाहिए और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करना चाहिए। परिवार में बच्चों को बचपन से ही जल बचाने की आदत सिखानी चाहिए।

डॉक्टर्स डे पर विशेष

आरबी त्रिपाठी

लेखक स्तंभकार हैं।

श्रेष्ठ उपचार के साथ पेशेंट का ख्याल रखने वाले डॉक्टर

डॉक्टर दिवस पर इस बार हम आपको इंदौर के एक श्रेष्ठ चिकित्सक और अपने क्लीनिक पर आने वाले हरेक पेशेंट का सदैव ख्याल रखने वाले डॉ. अजीत भट्ट से मिलवाते हैं। उनका आत्मीय व्यवहार और अधिक मेडिसिन की बजाय उचित सलाह देकर मार्गदर्शन करने वाले एम.डी. मेडिसिन, कार्डियोलॉजिस्ट तथा अच्छे फिजीशियन डॉक्टर भट्ट से हम चिकित्सक के रूप में उनकी लंबी पारी के अनुभवों को साझा कर रहे हैं।

डॉ. भट्ट का कहना है कि उनका मुख्य ध्येय और मकसद रहता है पेशेंट से अच्छा आत्मीय व्यवहार तथा ईमानदारी के साथ सबसे अच्छा और समय पर उपचार। जरूरतमंद लोगों के लिये मानवीयता से पेश आना और उन्हें अच्छी उपयुक्त सलाह देकर, फॉलोअप की सुनिश्चितता हमारे इस पेशे की सबसे बड़ी विशेषता है। इस बात का हम सदैव ध्यान रखते हैं। पेशेंट जब हमारे (किसी भी डॉक्टर के पास) क्लीनिक पर आते हैं तब वे अपनी स्वास्थ्य समस्या के साथ मानसिक रूप से भी परेशान नज़र आते हैं, ऐसे में उनसे सद्व्यवहार और सकारात्मकता के साथ चर्चा करना उनकी तकलीफ को आधे से ज्यादा तो वैसे ही ठीक कर देता है। यह पूर्ण मानवीयता के साथ एक थेरेपी की तरह काम करता है।

कोविड काल के मुश्किल दौर की याद करते हुए डॉ. भट्ट कहते हैं उस दौरान उन्होंने अनेक पेशेंट की चिकित्सकीय मदद की। यहां तक कि उनके पास उस वक्त मुंबई, पुणे, गुड़गांव और इंदौर, भोपाल समेत अन्य जगहों से फोन आते थे और वे टेलीफोनिक चर्चा में पेशेंट को उपचार तथा बरती जाने वाली ऐहतियात को लेकर सलाह देते थे। इस काम से उन्हें स्वयं भी आत्मसंतोष मिला। सचमुच वह सभी के जीवन का कठिनतम समय था। इसके अतिरिक्त भी वे अपने ऐसे पेशेंट जो क्लीनिक पर बार-बार नहीं आ सकते उन्हें भी टेलीफोन पर उपचार और व्हाटस एप पर मेडिसिन की जानकारी भेज देते हैं।

डॉक्टर भट्ट का कहना है कि उनका मुख्य ध्येय और मकसद रहता है पेशेंट से अच्छा आत्मीय व्यवहार तथा ईमानदारी के साथ सबसे अच्छा और समय पर उपचार। जरूरतमंद लोगों के लिये मानवीयता से पेश आना और उन्हें अच्छी उपयुक्त सलाह देकर, फॉलोअप की सुनिश्चितता हमारे इस पेशे की सबसे बड़ी विशेषता है। इस बात का हम सदैव ध्यान रखते हैं। पेशेंट जब हमारे (किसी भी डॉक्टर के पास) क्लीनिक पर आते हैं तब वे अपनी स्वास्थ्य समस्या के साथ मानसिक रूप से भी परेशान नज़र आते हैं, ऐसे में उनसे सद्व्यवहार और सकारात्मकता के साथ चर्चा करना उनकी तकलीफ को आधे से ज्यादा तो वैसे ही ठीक कर देता है। यह पूर्ण मानवीयता के साथ एक थेरेपी की तरह काम करता है।

हाल ही में 50 साल के एक पेशेंट को त्वरित रूप से उपचार मिल जाने से उसकी जीवन रक्षा के सीरियस केस का उल्लेख करते हुए डॉ. भट्ट बताते हैं कि वह उनके पास सीने में दर्द से पीड़ित होकर पहुंचा था, उन्होंने उसका चेकअप कर तत्काल एंजियोप्लासटी के लिये रिफर किया। चूंकि वह हार्ट डिजीज की दृष्टि से तीन घंटे का गोल्डन ऑवर था इसलिए तत्परता से ऑपरेशन हो जाने से उसका जीवन बचाया जा सका। इस मामले से उन्हें बहुत संतोष अनुभव हुआ।

यह आत्ममुग्धता की बात नहीं है लेकिन डाक्टर्स के किसी सीरियस पेशेंट को लेकर समय रहते फैसला लेने पर अमूल्य जीवन बचाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पेशेंट्स की सेवा के उद्देश्य से उन्होंने अपनी शासकीय सेवा से 9 साल पहले वीआरएस ले लिया था। एमडी मेडिसिन की डिग्री उन्होंने जबलपुर यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी।

अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में डॉ. भट्ट ज्यादा कुछ बताते नहीं लेकिन हमारे आग्रह पर उन्होंने इतना ही बताया कि उनके पिता जस्टिस एम. डी.भट्ट हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश रहे हैं। उनके दोनों बेटों ने चिकित्सा की बजाय फायनेंशियल सेक्टर में जाना उचित समझा जहां वे अच्छे पद पर कार्यरत हैं। डॉ. अजीत भट्ट की पत्नी डॉ. राजश्री भट्ट जानी- मानी गायकोनालॉजिस्ट हैं और इंदौर में ही प्रेक्टिस करती हैं।

डॉक्टर्स डे

योगेश कुमार गोयल

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

सफेद कोट में बसती है उम्मीद की सबसे बड़ी ताकत

चिकित्सकों के समाज के प्रति समर्पण एवं प्रतिबद्धता के लिए कृतज्ञता और आभार व्यक्त करने तथा मेडिकल छात्रों को प्रेरित करने के लिए प्रतिवर्ष एक जुलाई को 'राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस' मनाया जाता है। इस साल राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 'मुखौटे के पीछेः चिकित्सकों का उपचार कौन करता है?' विषय के साथ मनाया जा रहा है। यह विषय डॉक्टरों की भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक भलाई को स्वीकार करने और उसका समर्थन करने की आवश्यकता पर बल देता है, यह स्वीकार करते हुए कि उन्हें भी देखभाल और समर्थन की आवश्यकता है जबकि वे अपना जीवन दूसरों की देखभाल के लिए समर्पित करते हैं। वैसे चिकित्सक दिवस मनाने का मूल उद्देश्य चिकित्सकों की बहुमूल्य सेवा, भूमिका और महत्व के संबंध में आमजन को जागरूक करना, चिकित्सकों का सम्मान करना और साथ ही चिकित्सकों को भी उनके पेशे के प्रति जागरूक करना है। दरअसल कुछ चिकित्सक ऐसे भी देखे जाते हैं, जो अपने इस सम्मानित पेशे के प्रति ईमानदार नहीं होते लेकिन ऐसे चिकित्सकों की भी कमी नहीं, जिनमें अपने पेशे के प्रति समर्पण की कमी नहीं होती। बिना चिकित्सा व्यवस्था के इंसान की जिंदगी कैसी होती, इसकी कल्पना मात्र से ही रोम-रोम सिहर जाता है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में चिकित्सकों का महत्व सदा से रहा है और हमेशा रहेगा। भारतीय समाज में चिकित्सकों को भगवान के समान दर्जा दिया गया है। हालांकि यह अलग बात है कि निजी अस्पतालों में डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की भूमिका पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं लेकिन यह भी सच है कि चिकित्सक लोगों को विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों से निजात दिलाने में पूरी ताकत लगा देते हैं। भारत में चिकित्सक दिवस की स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी। पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री और जाने-माने चिकित्सक डॉ. बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में चिकित्सकों की उपलब्धियों तथा चिकित्सा क्षेत्र में नए आयाम हासिल करने वाले डॉक्टरों के सम्मान के लिए इसका आयोजन होता है। वे एक जाने-माने चिकित्सक, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और वर्ष 1948 से 1962 में जीवन के अंतिम क्षणों तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, बिधाननगर, अशोकनगर, कल्याणी तथा हबरा नामक पांच शहरों की स्थापना की थी। संभवतः इसीलिए उन्हें पश्चिम बंगाल का महान वास्तुकार भी कहा जाता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने वर्ष 1911 में एमआरसीपी और एफआरसीएस की डिग्री लंदन से ली। उन्होंने एक साथ फिजिशयन और सर्जन की रॉयल कॉलेज की सदस्यता हासिल कर हर किसी को अपनी प्रतिभा से हतप्रभ कर दिया था। वर्ष 1911 में भारत में ही एक चिकित्सक के रूप में उन्होंने अपने चिकित्सा कैरियर की शुरूआत की। वे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में शिक्षक नियुक्त हुए। वर्ष 1922 में वे कलकत्ता मेडिकल जनरल के सम्पादक और बोर्ड के सदस्य बने। 1926 में उन्होंने अपना पहला राजनीतिक भाषण दिया और 1928 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य भी चुने गए।

डॉ. बिधान चंद्र रॉय ने 1928 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के गठन और भारत की मेडिकल काउंसिल (एमसीआई) की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई बड़े-बड़े पदों पर रहने के बाद भी वे प्रतिदिन गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज किया करते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् उन्होंने अपना समस्त जीवन चिकित्सा सेवा को समर्पित कर दिया। बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं को आम जनता की पहुंच के भीतर लाने के लिए वे जीवन पर्यन्त प्रयासरत रहे। 4 फरवरी 1961 को उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया। 1967 में दिल्ली में उनके सम्मान में डॉ. बी.सी. रॉय स्मारक पुस्तकालय की स्थापना हुई और 1976 में उनकी स्मृति में केन्द्र सरकार द्वारा डॉ. बी.सी. रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की गई। संयोगवश डॉ. रॉय का जन्म और मृत्यु एक जुलाई को ही हुई थी। उनका जन्म 1 जुलाई 1882 को पटना में हुआ था और मृत्यु 1 जुलाई 1962 को हृदयाघात से कोलकाता में हुई थी।

भारत के अलावा दूसरे देशों में भी चिकित्सकों के सम्मान में ऐसे ही दिवस मनाए जाते हैं किन्तु वहां उनका आयोजन अलग-अलग तारीखों में होता है। वैसे चिकित्सक दिवस की शुरूआत सबसे पहले अमेरिका के जॉर्जिया में हुई थी। वहां चिकित्सकों के सम्मान के लिए एक दिन निश्चित करने का सुझाव जॉर्जिया निवासी डॉ. चार्ल्स बी एलमंड की पत्नी यूडोरा ब्राउन एलमंड ने 30 मार्च 1933 को दिया था। 30 मार्च 1958 को यूएस के हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स ने उनके उस सुझाव को स्वीकार करते हुए यह दिवस मनाना शुरू किया। वहां इसके लिए 30 मार्च की तारीख इसलिए रखी गई क्योंकि जॉर्जिया में इसी दिन डॉ. क्राफोर्ड डब्ल्यू लोंग ने पहली बार ऑपरेशन के लिए एनेस्थीसिया का उपयोग किया था। जहां अमेरिका में 30 मार्च को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, वहीं वियतनाम में इसकी स्थापना 28 फरवरी 1955 को हुई थी और वहां तभी से 28 फरवरी को या उसके आसपास वाले किसी दिन यह दिवस मनाया जाता है। ब्राजील में महान चिकित्सक रहे कैथोलिक चर्च के सेंट ल्यूक के जन्मदिवस के अवसर पर 18 अक्तूबर को जबकि क्यूबा में पीले बुखार पर शोध करने वाले चिकित्सक कार्लोस जुआन फिनले के जन्मदिवस 3 दिसम्बर को यह दिवस मनाया जाता है। नेपाल में यह दिवस नेपाल मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना के बाद 4 मार्च को तथा ईरान में महान चिकित्सक एविसेना के जन्मदिवस के अवसर पर 23 अगस्त को मनाया जाता है।

बहरहाल, चूंकि चिकित्सकों को पृथ्वी पर भगवान का रूप माना गया है, इसलिए समाज की भी उनसे यही अपेक्षा रहती है कि वे अपना कर्त्तव्य ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ निभाएं। हालांकि निजी अस्पतालों के कुछ चिकित्सकों पर मरीजों और उनके परिजनों के साथ लापरवाही और लूट के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। दरअसल निजी चिकित्सा तंत्र मुनाफाखोरी के व्यवसाय में परिवर्तित हो चुका है लेकिन फिर भी इस दीगर सच को भी नकारा नहीं जा सकता कि कोरोना हो या कैंसर, हृदय रोग, एड्स, मधुमेह इत्यादि कोई भी बीमारी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारियों से चिकित्सक ही करोड़ों लोगों को उबारते हैं। चूंकि चिकित्सक प्रायः मरीज को मौत के मुंह से भी बचाकर ले आते हैं, इसीलिए चिकित्सकों को भगवान का रूप माना जाता रहा है। चिकित्सा केवल पैसा कमाने के लिए एक पेशा मात्र नहीं है बल्कि समाज के कल्याण और उत्थान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। इसीलिए चिकित्सक को सदैव सम्मान की नजर से देखने वाले समाज के प्रति उनसे भी समर्पण की उम्मीद की जाती है।

पुलिस मुख्यालय परिवार द्वारा 11 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी गई भावभीनी विदाई

पुलिस महानिदेशक ने भी को स्मृति चिन्ह भेंट कर किया सम्मानित

भोपाल। पुलिस मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं से माह जून में सेवानिवृत्त 11 कर्मचारियों को पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाणा ने मंगलवार को भावभीनी विदाई दी। पुलिस महानिदेशक ने सभी को पौधे एवं

स्मृति चिन्ह भेंट किए और उनके स्वस्थ एवं सुखी जीवन की कामना की। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके विभिन्न स्वत्व (क्लेम) भुगतान के आदेश भी प्रदान किए गये।

नवीन पुलिस मुख्यालय भवन कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित विदाई समारोह में विशेष पुलिस महानिदेशक श्री आदर्श कटियार, श्री पंकज श्रीवास्तव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सोलोमन यश कुमार मिंज, पुलिस महानिरीक्षक श्री हरिनारायणचारी मिश्र एवं अन्य पुलिस अधिकारी, कर्मचारी एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिजन उपस्थित थे।

पुलिस मुख्यालय से सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक अ.अ.वि. श्रीमती शहनाज खान, निरीक्षक विशेष शाखा श्री प्रकाश नारायण लाम्बे, कार्यवाहक निरीक्षक एससीआरबी श्री संतोष कुमार सेन, कार्यवाहक आंकिक/सूबेदार (एम) प्रशिक्षण श्री जुल्फिकार अली खान, आंकिक/सूबेदार (एम) कार्मिक श्रीमती सुमन अमोली, उप निरीक्षक अ. अ. वि. श्री आनंदीलाल, उप निरीक्षक अ.अ.वि. श्री भानसिंह यादव, उप निरीक्षक एससीआरबी श्री प्रकाश राजपूत, उप निरीक्षक (एम) अ.अ.वि. श्रीमती स्मिता दाणी, कार्यवाहक उप निरीक्षक विशेष शाखा श्री राजेन्द्र प्रसाद निगम तथा आरक्षक (एम) रा.औ.सु.बल सुश्री सुषमा रैकवार को पुलिस मुख्यालय परिवार ने मंगलवार को भावभीनी विदाई दी।

सहायक पुलिस महानिरीक्षक श्रीमती अंशुमान अग्रवाल ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कार्यकाल की जानकारी दी। विदाई समारोह में मौजूद अधिकारियों ने सेवानिवृत कर्मचारियों की मेहनत और लगन की सराहना की।

मोहन सरकार की मंत्री प्रतिमा बागरी को नोटिस

6 जुलाई को छानबीन समिति के समक्ष जाति प्रमाण-पत्र के साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे

भोपाल (नप्र)। प्रदेश की नगरीय प्रशासन राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण-पत्र विवाद में राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने उन्हें नोटिस जारी किया है। समिति ने मंत्री बागरी को 6 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

मंत्री बागरी से कहा गया है कि छानबीन समिति के समक्ष उपस्थित होने के दौरान वे वर्ष 1950 की स्थिति के अनुसार सतना (मध्य प्रदेश) के निवासी होने तथा स्वयं को बागरी अनुसूचित जाति का सदस्य होने संबंधी प्रमाण-

पत्र प्रस्तुत करें। इसके लिए सभी आवश्यक दस्तावेज छानबीन समिति के समक्ष पेश करने होंगे। जनजातीय कार्य विभाग के आयुक्त कार्यालय ने यह नोटिस मंगलवार को जारी किया है। यह नोटिस बागरी के जाति प्रमाण-पत्र को लेकर की गई शिकायत पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा छानबीन समिति को 60 दिन के भीतर प्रमाण-पत्र की वैधता पर निर्णय लेने के निर्देश दिए जाने के मद्देनजर जारी किया गया है। इस नोटिस के बाद राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी का जाति प्रमाण-पत्र विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

एससी कांग्रेस के अध्यक्ष ने दायर की है याचिका

इससे पहले हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता एवं एससी कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार की याचिका पर यह आदेश दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि छानबीन समिति संबंधित पक्ष को बुलाकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच करेगी और यह तय करेगी कि प्रतिमा बागरी के पक्ष में जारी अनुसूचित जाति (एससी) का प्रमाण-पत्र वैध है या नहीं। जांच पूरी होने के बाद समिति उचित आदेश पारित करेगी। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि यदि 30 जून 2026 तक समिति कोई निर्णय नहीं लेती है, तो याचिकाकर्ता को इस याचिका को पुनर्जीवित (रिवाइव) कराने की स्वतंत्रता होगी।

गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की हुई समीक्षा

तय समय में पूर्ण करें कार्य, ढिलाई बर्दाश्त नहीं : राज्यमंत्री गौर

भोपाल। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने मंगलवार को मंत्रालय में गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण की जाएं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही और अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा दोषी एजेंसियों और ठेकेदारों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि बावड़िया कला चौराहा (अपोलो सेज अस्पताल) से ऑशिमा मॉल तक प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तथा इसी माह के अंत तक निर्माण कार्य प्रारंभ होने की संभावना है। इस पर राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कार्य को गति देने के निर्देश दिए।

उन्होंने बाबूलाल गौर सेतु, बावड़िया में प्रस्तावित मरम्मत एवं लेफ्ट टर्न निर्माण कार्य बारिश के बाद तत्काल प्रारंभ करने को कहा। पिपलानी से खजूरी रोड निर्माण कार्य की समीक्षा के दौरान बताया गया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है तथा नाली निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। लंबे समय से लंबित इस परियोजना पर नाराजगी व्यक्त करते हुए श्रीमती गौर ने संबंधित ठेकेदार की लापरवाही पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

खेजड़ा बरामद पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि पहले सड़क निर्माण पूरा किया जाए, उसके

बाद पोल शिफ्टिंग एवं विद्युत व्यवस्था से जुड़े कार्य किए जाएं। ग्लोबल स्किल पार्क के समीप पुलिया एवं अतिक्रमण के कारण मार्ग निर्माण बाधित होने पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में शीघ्र अतिक्रमण हटाकर निर्माण कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिये।

राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने पुलिस थाना बागसेवनिया से एचडीएफसी बैंक तक मार्ग, गुलमोहर से आकृति इको सिटी, अरविंद विहार कॉलोनी मार्ग, बागमुगालिया एक्सटेंशन मार्ग, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कटारा हिल्स-गायत्री विहार-नंदगांव मार्ग, आदर्श नगर-प्रधान मंडपम-साधना एन्क्लेव मार्ग, कुंजन नगर फेस-1 से बागसेवनिया सीसी नहर रोड, अवधपुरी क्रिस्टल आइडियल गेट तक मार्ग, स्वर्ण जयंती पार्क से गुलमोहर मार्ग, बाबरिया चौराहे से विरासा हाइट्स मार्ग, अयोध्या बायपास से ग्राम कोलुआ करारिया मार्ग, एम्स अस्पताल से डीआरएम पहुंच मार्ग तथा साकेत नगर स्थित सागर पब्लिक स्कूल से 9 बीडीए कॉम्प्लेक्स तक क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की भी विस्तृत समीक्षा की।

राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने निर्देश दिए कि जिन कार्यों की स्वीकृति मिल चुकी है, उन्हें तत्काल प्रारंभ किया जाए और प्रगति पर सतत निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि जनसुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तय समय-सीमा में कार्य पूर्ण कर जनता को राहत पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में लोक निर्माण विभाग, नगर निगम तथा विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

7 बच्चों ने 7 साल की लड़की से बेड-टच किया

बहला-फुसलाकर सुनसान जगह ले जाने का आरोप; बच्ची का मेडिकल कराया

छिंदवाड़ा (नप्र)। छिंदवाड़ा शहर के महिला थाना क्षेत्र में 7 साल की एक बच्ची के साथ 'बैड टच' (छेड़छाड़) का मामला सामने आया है। बच्ची के साथ यह हरकत करने के आरोप में 9, 10 और 11 साल की उम्र के सात नाबालिगों को पुलिस ने राउंडअप किया है। घटना सोमवार 29 जून की है। पीड़ित बच्ची अपने घर के पास एक सामाजिक कार्यक्रम में गई थी। इस दौरान वहां मौजूद कुछ नाबालिग बच्चे उसे बहला-फुसलाकर पास ही एक मकान के पीछे सुनसान जगह पर ले गए। आरोप है कि वहां बच्चों ने उसके साथ बैड टच किया। पीड़ित बच्ची अपने घर के पास एक सामाजिक कार्यक्रम में गई थी।

घर पहुंचकर परिजन को बताई पूरी बात- घटना के बाद बच्ची काफी डरी-सहमी हालत में घर पहुंची। उसने रोते हुए परिजन को पूरी घटना बताई। बच्ची की बात सुनकर परिवार के लोग घबरा गए। बिना देर किए वे उसे महिला थाना लेकर पहुंचे और पूरे मामले की लिखित शिकायत दी।

शिकायत मिलते ही पुलिस ने की कार्रवाई- महिला थाना प्रभारी अरुणा वहाने ने बताया कि परिजन की शिकायत मिलते ही विधि सम्मत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच शुरू की और घेराबंदी कर घटना में शामिल बताए जा रहे सातों बच्चों को राउंडअप कर लिया।

बच्ची का मेडिकल कराया, रिपोर्ट बाकी

पुलिस ने पीड़ित बच्ची का मेडिकल परीक्षण भी कराया है। फिलहाल रिपोर्ट आनी बाकी है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट मिलने के बाद स्पष्ट होगा कि आगे किन धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

राज्य स्तरीय मिनी सब जूनियर बैडमिंटन स्पर्धा में धार की अद्वितिया शर्मा अंडर 13 बालिका एकल एवं युगल वर्ग में उप-विजेता

धार। 'गोल्डन ट्राफी' म.प्र राज्य स्तरीय मिनी सब जूनियर बैडमिंटन स्पर्धा में धार की अद्वितिया शर्मा ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए अंडर 13 बालिका एकल एवं युगल वर्ग में राज्य उप विजेता का खिताब जीता। सुधीर वर्मा बैडमिंटन प्रशिक्षक ने बताया अंडर 13 बालिका एकल वर्ग के फाइनल मुकाबले में भोपाल की समायरा सक्सेना ने अद्वीतिया शर्मा को हर्षवर्धनसिह को 15-07,15-09 से पराजित किया। अंडर 13 बालिका युगल वर्ग के फाइनल मुकाबले में राधवी गुप्ता एवं अनवी विंदु की जोड़ी ने अद्वीतिया शर्मा एवं ओमीशा मेहता को 15-7,15-10 से पराजित किया। स्पर्धा में ग्रुप के उभरते नन्हे शटलर लवाश पटौदिया ने अपने सर्वश्रेष्ठ खेल का प्रदर्शन करते हुए अंडर 11 बालक एकल वर्ग में सेमीफाइनल खेले। निहिरा पटौदिया , लविका डोडिया प्रभास शर्मा भी अपने अपने आयु वर्ग में सेमीफाइनल खेले। सोरभ सिसौदिया, जयदीप बौरासी, आदित्य गुप्ता, हिमांश जाट, आनंद मौरे तनुज हरोड युगल वर्ग में क्वाटर फाइनल खेले।स्पर्धा में लायरा लशकरी,नेविका राठोर,सिद्धाशी पोरवाल,मिशिता महाजन,एशनी प्रजापत ,जान्हवी जांगड़े, भाग्य श्री,नविका गुप्ता,आर्या अग्रवाल, काव्या,भवनीश चौहान,नित्याश जाट,वेदाश प्रजापत, जयवर्धनसिह, रिदान गुप्ता हिमांक सक्सेना, वरुण वर्मा,अनमोल गुजाल, प्रियांशु बारिया, मोलिक राठोर, आदेश कटारे, अभिराज कटारे,मोहनिश महाजन आदि ने भी स्पर्धा में भाग ले कर श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। अद्वितिया की उक्त राज्य स्तरीय उपलब्धि पर डीडीबीए के अध्यक्ष छोटू शास्त्री, लिटिल शटलर ग्रुप अध्यक्ष शरदचन्द्र निगम, राजेश शाक्य डीएसओ धार, सलीम खान सचिव डीडीबीए, भूपेंद्र जोशी सचिव लिटिल शटलर ग्रुप, राजीव जोशी , भूपेंद्रसिंह राजावत, सहित ग्रुप के सभी पालकगणो ने बधाई दी।

सभ्यता बदलती रहती है, संस्कृति कभी नहीं बदलतीं है : दिनेश तेजरा

● मीसाबंदी भंवरलाल राजपुरोहित विचार मंच व्याख्यान का द्वितीय सोपान

धार। देश की हजारों वर्षों की एक गौरवमयी यात्रा का नाम है हिन्दुत्व । यह यात्रा कभी वैदिक, कभी सनातनी कभी इंडियन के नाम से चलती रही। नाम बदलते रहे, मगर आत्मा कभी नहीं बदली। हिन्दुत्व की वजह से ही देश आज भी जीवित है। आज देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए देश की आत्मा को बचाना होगा । उद्गार मीसाबंदी भंवरलाल राजपुरोहित विचार मंच द्वारा आयोजित व्याख्यान में राष्ट्रीय स्वंसेवक संघ के धार विभाग के विभाग प्रचारक दिनेश तेजरा ने व्यक्त किए ।

'हिन्दुत्व एक विचार, एक संस्कृति, एक जीवन दृष्टि ' विषय पर बोलते हुए श्री तेजरा ने बताया कि जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, कर्तव्य हैं, धर्म है वही हिन्दुत्व है। भारत की सभ्यता दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यता रही है। सभ्यता किसी भी राष्ट्र की भौतिक अवस्था होती है,सभ्यता बदलती रहती है, मगर संस्कृति कभी बदलती नहीं है। हिन्दुत्व एवं धर्म की व्याख्या को समझाने के लिए उन्होंने गुरु गोविन्द सिंह, बाजीराव पेशवा , स्वामी विवेकानंद, तुलसीदास,कबीर तथा आद्य शंकराचार्य के जीवन दर्शन को भी आधार बनाया।

कार्यक्रम के अध्यक्ष राधेश्याम यादव ने आपातकाल की विभीषिका पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आपातकाल की ज्यादतियों ने ब्रिटिश हुकूमत की याद को ताजा कर दिया। लेकिन जेल की सलाखों में रहने वाले लाखों देशभक्त डिगे नहीं । यही कारण है कि आज हम लोकतंत्र की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। कार्यक्रम में मीसाबंदियो के साथ दिवंगत मीसाबंदी परिवारों का भी सम्मान अतिथियों द्वारा किया गया। अतिथियों के साथ विचार मंच के संयोजक उदय वडनेरकर एवं सह संयोजक लीलाधर दांदक भी मंचासीन थे। अतिथियों का स्वागत सुरेश, राकेश, नरेश राजपुरोहित, शरद पुरोहित, बृजकिशोर बोड़ा, नंदराम टांक, राजेश हारोड़, शशि श्रीवास्तव, आशीष शर्मा तथा शैलेन्द्र तिवारी ने किया। देवेन्द्र सोनोने ने मीसाबंदी स्व. भंवरलालजी राजपुरोहित का परिचय तथा अतिथि परिचय राजेन्द्र शर्मा ने दिया। समिति सदस्य विनोद नाभावंशी ने बताया कि आयोजन में धार नगर के दिवंगत मीसाबंदी परिवारों का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर मीसाबंदी विक्रम वर्मा, भारत महाजन, समिति के वरिष्ठ सरदार सिंह तवर, दीपक खुलत्कर, विधायक नीना वर्मा, मीसबंदी परिवारजन तथा बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अंशुल राजपुरोहित ने तथा डॉ. श्रीकांत द्विवेदी ने आभार व्यक्त किया।

जिले में 6 जुलाई तक मनाया जाएगा सहकारिता सप्ताह

सहकारी समितियों में सुशासन, जनभागीदारी एवं जागरूकता को मिलेगा बढ़ावा

धार। प्रदेश में 29 जून से 6 जुलाई तक ''सहकारी सप्ताह'' का गरिमामय आयोजन किया जा रहा है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर सहकारिता की भावना को सुदृढ़ करना तथा शासन की कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाना है। इस दौरान राष्ट्रीय, राज्य, जिला, विकासखंड तथा प्राथमिक सहकारी समितियों के स्तर पर सहकारिता आंदोलन को जन-जन तक पहुँचाने, सहकारी संस्थाओं की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने तथा आमजन की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि विपणन सम्मेलन के अंतर्गत विपणन समितियां, पैक्स एवं एफपीओ का संयुक्त संवाद तथा सहकारी से समृद्धि की परिकल्पना में कृषि विपणन अभियान का आयोजन, सहकारी बैंकों/पैक्स के व्यवसाय संवर्धन अंतर्गत नवीन सदस्य बनाने/केसीसी जारी करने तथा क्यूआर कोड आधारित विशेष वसूली अभियान का क्रियान्वयन, दुग्ध सहकारी संस्थाओं में महिला सदस्यों का सहकारी सम्मेलन, महिला उद्यमियों का सम्मान, खाद्य प्रसंस्करण एवं मिलेट उत्पाद प्रदर्शनिय सीपीपीपी मॉडल पर सहकारिता में निवेश की संभावनाओं तथा वर्तमान उपलब्धियां एवं सहकारी बीज व्यवसाय में नये प्रयोग/नवाचार संबंधी

गतिविधि का आयोजन, मत्स्य, दुग्ध, वनोपज, बीज एवं श्रमिक समितियों की भूमिका पर संगोष्ठी तथा मत्स्य उत्पादन एवं विपणन विषयक प्रदर्शनिया, पौधारोपण भी किया जायेगा।

सहकारिता सप्ताह के अंतर्गत जिले की प्रत्येक पैक्स में ध्वजारोहण एवं उपविधि का वाचन किया जायेगा। सप्ताह भर पौधारोपण, सहकारिता विकास विषयक गोष्ठियां, व्याख्यान माला, सहकार संकल्प दौड़, मृदा स्वास्थ्य परीक्षण तथा सहकारिता जागरूकता अभियान जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने के लिए ड्रोन के माध्यम से तरल उर्वरक के छिड़काव का प्रदर्शन, माइक्रो एटीएम के उपयोग की जानकारी, नए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) एवं रूपे कार्ड का वितरण भी किया जाएगा। आयोजन का उद्देश्य किसानों को तकनीक, डिजिटल बैंकिंग और सहकारिता की योजनाओं से जोड़कर उन्हें अधिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना है।

सहकारिता विभाग ने जिले के सभी सहकारी संस्थानों, किसानों, दुग्ध उत्पादकों, मत्स्य पालकों, जनप्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों तथा आम नागरिकों से अपील की है कि वे 'सहकारी सप्ताह' के दौरान आयोजित कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता निभाकर 'सहकार से समृद्धि, सशक्त समाज, सशक्त भारत' के संकल्प को मजबूत बनाने में अपना योगदान दें।

सहकारिता की भावना को सुदृढ करने के उद्देश्य से सहकारी सप्ताह के अंतर्गत कलेक्टर ने जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी....

'सहकारी सप्ताह' के गरिमामय आयोजन की कड़ी में 29 जून को कलेक्टर राजीव रंजन मीना द्वारा सहकारिता की भावना को सुदृढ करने एवं किसानों और ग्रामीण विकास को नई दिशा देने के संकल्प के साथ प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। यह प्रचार वाहन जिले में शासन की कल्याणकारी योजनाओं का जन-जन तक प्रचार-प्रसार करेंगा। इस अवसर पर उपायुक्त सहकारिता एवं बैंक प्रशासक वर्षा श्रीवास व बैंक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, धार के.के. रायकवार सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी मौजूद थे।

'छात्रों की गूंज'

हम शहर के सपनों, भविष्य को सुनना चाहते थे, मेहनत करने वालों के सम्मान का कार्यक्रम है, 50 मेधावी सम्मानित

सोहागपुर। कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के अंतर्गत 'प्रतिभा सम्मान समारोह प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के आतिथ्य में गरिमामय कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर सोहागपुर विधानसभा चुनाव प्रत्याशी रहे पुष्पराज सिंह पटेल, समाजसेवी हरगोविंद पुरबिया, पूर्व नपाध्यक्ष संतोष मालवीय, ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष सुधीर ठाकुर ,जले शर्मा आदि विशेष रूप से उपस्थित थे। इस गरिमामय कार्यक्रम में प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं ने अपने अनुभवों को साझा किया। जिसमें छात्र छात्राओं ने जीवन में क्या बनना चाहते क्या करना चाहते पर सारगर्भित उद्बोधन दिए गए। इस उत्कृष्ट प्रतिमा सम्मान समारोह में अभिभावकों में प्रसन्नता देखी गई।इस अवसर पर पुष्पराजसिंह पटेल ने कहा कि हम शहर के सपनों को सुनना चाहते थे। भविष्य को सुनना

चाहते थे। इसी कारण उक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपने सरकार पर कटाक्ष करते कहा कि 12, पन्द्रह सालों से पेपर लीक हो रहें। इससे छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है।कई छात्र ,छात्राएं ओवर एज हो गए। ऐसा लगता है यह जानबूझकर कराया जाता है। आपने सभी को आश्वस्त किया कि इस जो कार्यक्रम आयोजित किया है।आने वाले समय इससे अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस गरिमामय कार्यक्रम नगर के करीबन 50 मेधावी विद्यार्थियों को उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक और अन्य उपलब्धियों के लिए तालियों के बीच सम्मानित करके उत्साहवर्धन किया गया। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष प्रशांत जायसवाल, इरफान खान, नीरज चौधरी, पार्षद मोहन कहार, पार्षद भास्कर मांझी, प्रांजल तिवारी, ऋषभ दीक्षित, देवांशु शुक्ला, अनंत तिवारी, देवांक सराठे, कमलेश मालवीय, जयभानु सिंह चंदेल, अल्ताफ खान सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

संक्षिप्त समाचार

कलेक्टर के निर्देशानुसार एसडीएम इटारसी ने किया मूंग उपार्जन के लिए प्रस्तावित कार्यों का निरीक्षण

नर्मदापुरम (निप्र)। आगामी मूंग उपार्जन सीजन को सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं किसान हितैषी बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) इटारसी श्री नीलेश शर्मा ने क्षेत्र के विभिन्न वेयरहाउसों का सघन निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान नीलम एग्रो, रामकृष्ण, दादाजी सहित अन्य वेयरहाउसों का अवलोकन किया गया। जिले में शीघ्र प्रारंभ होने वाले मूंग उपार्जन कार्य के मद्देनजर कलेक्टर द्वारा उपयुक्त स्थलों को उपार्जन केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम श्री नीलेश शर्मा ने खंड स्तरीय उपार्जन समिति के सदस्यों के साथ वेयरहाउसों में उपलब्ध स्कंध (स्टॉक) की स्थिति, उपार्जन केंद्रों तक पहुंचने वाले एप्रोच रोड, नवीन उपार्जन केंद्र स्थापित करने के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं तथा अन्य व्यवस्थाओं का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि उपार्जन प्रक्रिया के दौरान किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। निरीक्षण के दौरान खंड स्तरीय उपार्जन समिति के सदस्य श्री हितेश साहू, श्री सुनील उइके, श्री विनोद बिसारे सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत बावड़ी पूजन कर दिया जल संरक्षण का संदेश

सीहोर (निप्र)। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जन अभियान परिषद द्वारा सीहोर के मनकामेश्वर मंदिर पर 'बावड़ी उत्सव' कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बावड़ी का पूजन किया गया और सभी ने जल संरक्षण की शपथ ली तथा जल स्त्रोतों के संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर सीहोर ब्लॉक समन्वयक श्री प्रदीप सेंगर, श्री अनिल सक्सेना सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

वर्षाकाल में अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध, मुख्यालय छोड़ने से पहले लेनी होगी अनुमति

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने वर्षाकाल के दौरान संभावित आपात स्थितियों एवं जनहित से जुड़े कार्यों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह निर्देश सोमवार को आयोजित टीएल बैठक में दिए। कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि बारिश के मौसम में राहत एवं बचाव कार्यों, पेयजल व्यवस्था, सड़क संपर्क, जलभराव तथा अन्य आवश्यक सेवाओं की सतत निगरानी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना आवश्यक है। ऐसे में सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने दायित्वों के प्रति सजग रहें तथा बिना अनुमति अवकाश पर न जाएं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। मुख्यालय छोड़ने अथवा विशेष परिस्थितियों में अवकाश स्वीकृति के लिए अपर कलेक्टर एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) को अधिकृत किया गया है। कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों से कहा कि वे अपने अधीनस्थ अमले की उपलब्धता सुनिश्चित करें तथा वर्षाकाल के दौरान किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां बनाए रखें, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो और प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुचारु रूप से संचालित होती रहें।

जनप्रतिनिधियों एवं कलेक्टर ने 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पिलाई पोलियो की दो बूंद दवा

नर्मदापुरम (निप्र)। जिले में 28 से 30 जून तक संचालित होने वाले पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ रविवार को जिला अस्पताल परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किया गया। इस अवसर पर लोकसभा सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी, राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया एवं कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दो बूंद दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की।

कलेक्टर बोले- पीने के पानी की नियमित जांच एवं नलकूपों का क्लोरीनेशन सुनिश्चित करें

वर्षाकाल के दृष्टिगत जर्जर मकानों को ध्वस्त करें

- मूंग उपार्जन की तैयारियां समय पर पूरी करें, पंजीयन सत्यापन में न बरतें लापरवाही - कलेक्टर
- हितग्राहियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बैंक खातों का स्वयं करें सत्यापन - कलेक्टर
- कलेक्टर की अध्यक्षता में टीएल बैठक आयोजित

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में टीएल बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने सभी विभागों के समय-सीमा वाले प्रकरणों और सीएम हेल्पलाइन में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की और समय सीमा के भीतर सभी प्रकरणों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय कर्मचारियों की सभी विभागीय सेवानिवृत्ति संबंधी कार्यवाही समय-सीमा में पूरी करते हुए उनके समस्त स्वत्वों एवं देयकों का भुगतान पूरी तत्परता से सुनिश्चित किया जाए। सेवानिवृत्ति से संबंधित किसी भी कार्रवाई में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया में मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं। ये कर्मचारी वर्षों तक शासन की सेवा करते हैं, इसलिए उनके सम्मान और अधिकारों का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी स्मरण कराया कि प्रत्येक शासकीय सेवक को एक दिन सेवा से सेवानिवृत्त होना है, इसलिए इस कार्य को संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ प्राथमिकता देते हुए समय पर पूरा करें। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने टीएल बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों के बैंक खातों का सत्यापन बैंक पासबुक के आधार पर स्वयं करें। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के भुगतान अथवा राशि अंतरण से पहले बैंक खाते की जानकारी का भौतिक सत्यापन किया जाए। बैंक पासबुक से सत्यापन करने पर किसी भी प्रकार की त्रुटि या गड़बड़ी की संभावना नहीं रहेगी तथा संबंधित राशि सीधे वास्तविक हितग्राही के बैंक खाते में ही अंतरित होगी। बैठक मे जिला पंचायत सीईओ श्रीमती सर्जना यादव, संयुक्त कलेक्टर श्री रविंद्र परमार, एसडीएम श्री तन्मय वर्मा, श्रीमती स्वाति मिश्रा सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिये जर्जर मकानों को गिराने निर्देश : बैठक में कलेक्टर ने वर्षाकालीन आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी एसडीएम एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिए कि दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए चिन्हित सभी जर्जर मकानों को तत्काल गिराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जनहानि रोकना सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए जोखिम वाले भवनों के संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि बाढ़, अतिवृष्टि, प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की कार्रवाई भी पूरी तत्परता से की जाए। उन्होंने कहा कि राहत प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर पीड़ित व्यक्ति या उनके परिजनों तक समय पर सहायता राशि पहुंचाई जाए, ताकि संकट की घड़ी में उन्हें तत्काल राहत मिल सके। इसके साथ ही किसी भी जर्जर भवन में स्कूल, आंगनबाड़ी न लगाये। यदि कोई भवन जर्जर हो तो उस स्कूल, आंगनबाड़ी को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाये।

अन्य निर्देश : टीएल बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में किसानों की आवश्यकता के अनुसार खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा खाद का वितरण ई-टोकन प्रणाली के माध्यम से व्यवस्थित ढंग से किया जाए। किसी भी किसान को खाद प्राप्त करने के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और वितरण प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी एवं सुचारु रहे। बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि जिले में किसानों की मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने संबंधित अधिकारियों को वनाधिकार पट्टों के फौती नामांतरण तथा वन ग्रामों के राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन की कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय कार्यालयों एवं भवनों के निर्माण के लिए वास्तव में जितनी भूमि की आवश्यकता हो, उतनी ही भूमि आवंटन का प्रस्ताव भेजा जाए।

मूंग पंजीयन का सत्यापन और केन्द्रों में आवश्यक व्यवस्था के निर्देश

कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समर्थन मूल्य पर मूंग उपार्जन के लिए किसानों के पंजीयन का सत्यापन समय-सीमा में पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ किया जाए। पात्र किसानों का पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। कलेक्टर ने उपार्जन केंद्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को उपज विक्रय के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए केंद्रों पर पेयजल, छाया, बैठने की व्यवस्था, पर्याप्त तौल कांटे, बारदाना तथा अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध रहें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य करते हुए उपार्जन प्रक्रिया को सुचारू, पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए।

पीने के पानी की नियमित जांच एवं नलकूपों का क्लोरीनेशन करें

कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल निगम, सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्षाकाल को देखते हुए पेयजल की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। पीने के पानी की नियमित जांच कराई जाए तथा जल स्रोतों की सतत निगरानी सुनिश्चित की जाए। जिले के सभी नलकूपों का समय.समय पर क्लोरीनेशन कराया जाए ताकि जल जनित बीमारियों की रोकथाम हो सके और नागरिकों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पेयजल संबंधी शिकायतों का तत्काल निराकरण करें तथा किसी भी क्षेत्र में दूषित जल की स्थिति उत्पन्न न होने दें।

रैन बसेरों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश

कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने जिले के सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के सभी रैन बसेरों में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं एवं व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। रैन बसेरों में साफ-सफाई, पेयजल, विद्युत, शौचालय सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं की नियमित व्यवस्था बनाए रखी जाए, ताकि वहां ठहरने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि रैन बसेरों का नियमित निरीक्षण किया जाए तथा जहां भी किसी प्रकार की कमी या अव्यवस्था हो, उसका तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी रैन बसेरे सुव्यवस्थित एवं उपयोग के लिए सदैव तैयार रहें।

घर-घर पहुंचकर पिलाई जा रही पोलियो की दवा

विदिशा (निप्र)। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के दूसरे दिन स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल टीमें घर-घर पहुंचकर शून्य से पांच वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को पोलियो रोधी दवा की खुराक पिलाने का कार्य कर रही हैं। अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा पोलियो की जीवनरक्षक खुराक से वंचित न रह जाए।

इसी क्रम में मोबाइल टीम के फील्ड वर्कर श्री फिरोज खान ने गोकुल धाम कॉलोनी सहित विभिन्न क्षेत्रों में घर-घर जाकर उन बच्चों का सर्वे एवं ट्रैकिंग की, जो अभियान के पहले दिन किसी कारणवश पोलियो बूथों तक नहीं पहुंच पाए थे। टीम द्वारा ऐसे परिवारों से संपर्क कर बच्चों को उनके घर पर ही पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। गोकुल धाम कॉलोनी में निवासरत दिनेश अहिरवार की पुत्री पिहू अहिरवार तथा जगमोहन शर्मा के एक वर्षीय पुत्र रुद्ध शर्मा को टीम द्वारा घर पहुंचकर पोलियो रोधी दवा की खुराक पिलाई गई। इसके साथ ही अन्य छूटे हुए बच्चों की पहचान कर उन्हें भी अभियान से जोड़ा जा रहा

है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत मोबाइल और ट्रांजिट टीमें लगातार सक्रिय हैं तथा घर-घर भ्रमण कर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिले का कोई भी पात्र बच्चा पोलियो की दवा से वंचित न रहे। अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वे अपने पांच वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो की प्रत्येक खुराक अवश्य दिलाएं, ताकि पोलियो मुक्त भारत के संकल्प को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।

अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध प्रशासन की सख्त कार्रवाई

अनुविभाग सिवनिमालवा में आदतन अतिक्रमणकरियों को भेजा गया जेल

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में शासकीय एवं निजी भूमियों से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। अनुविभाग सिवनी मालवा के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों, जनसुनवाई एवं सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से मिली शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जों को हटाने का अभियान निरंतर जारी है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी मालवा श्री विजय राय ने बताया कि अभियान के तहत जहां शासकीय भूमि से अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं, वहीं निजी स्वामित्व की भूमि पर बलपूर्वक किए गए अवैध कब्जों के मामलों में भी नियमानुसार सीमांकन, स्थलीय जांच एवं सक्षम न्यायालय के आदेशों के आधार पर बेदखली की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

इसी क्रम में शिवपुर थाना क्षेत्र के ग्राम उमरिया निवासी कृषक श्रीमती रेशमबाई की निजी कृषि भूमि पर हुकुम सिंह पिता रूपसिंह यदुवंशी द्वारा लंबे समय से अवैध कब्जा किया जा रहा था। राजस्व विभाग द्वारा पूर्व में कई बार बेदखली कर पीड़ित कृषक को भूमि का कब्जा दिलाए जाने के

बावजूद संबंधित व्यक्ति द्वारा पुनः अवैध अतिक्रमण किया जाता रहा। न्यायालय के आदेशों की लगातार अवहेलना एवं आदतन अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम श्री विजय राय ने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250(2) के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई करते हुए संबंधित अतिक्रमणकारी को विधिवत सिविल जेल भेजा गया।

एसडीएम श्री विजय राय ने बताया कि शासकीय अथवा निजी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्राम चौतलाय, ग्वाड़ी, पीपलठोन एवं चापड़ाग्रहण सहित अन्य ग्रामों में भी शासकीय भूमि एवं सार्वजनिक रास्तों पर अवैध कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध सिविल जेल वारंट जारी किए गए हैं। पुलिस एवं राजस्व विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिवनिमालवा में अतिक्रमण के विरुद्ध यह अभियान निरंतर जारी रहेगा तथा कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

शासन की योजनाओं का नागरिकों तक सुगमता से पहुंचे लाभः कलेक्टर विश्वकर्मा

- टीएल बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने की सीएम हेल्पलाईन, योजनाओं तथा शासकीय कार्यो की समीक्षा

रायसेन (निप्र)। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित टीएल बैठक में कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा समयसीमा वाले शासकीय पत्रों, सीएम हेल्पलाईन तथा शासन की योजनाओं और अभियानों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा कर अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक के प्रारंभ में उन्होंने सभी जिला अधिकारियों तथा विकासखण्ड अधिकारियों से कहा कि शासन की योजनाओं का पूरी गंभीरता के साथ प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए, जिससे कि नागरिकों को सुगमता से योजनाओं का लाभ मिले। बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सभी तहसीलदारों से कहा कि प्रकरणों का समयावधि के पहले ही निराकरण सुनिश्चित कराएं। फार्मर रजिस्ट्री की तहसीलवार जानकारी लेते हुए अधिकारियों को सौ फीसदी कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही सभी एसडीएम को नियमित मॉनीटरिंग करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की अधिकारियों से जानकारी लेते हुए कहा कि प्राप्त आवेदनों पर शीघ्रता से निराकरण कर प्रतिवेदन जिला कार्यालय पर भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने धारणाधिकार के आवेदनों को भी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। सीएम हेल्पलाईन शिकायतों की विभागवार और अधिकारीवार समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाईन शिकायतों का समयावधि में संतुष्टिपूर्ण निराकरण कराएं। उन्होंने ऊर्जा विभाग, कृषि विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग तथा शिक्षा विभाग की सीएम हेल्पलाईन नॉन अटेन्डेन्डेट रहते हुए अगले लेवल पर प्रेषित होने पर नाराजगी जाहिर कर संबंधित अधिकारियों को गंभीरता दिखाते हुए कार्य करने के लिए निर्देशित किया। इसी प्रकार आठ शिकायते निम्न गुणवत्ता से बंद होने पर भी नाराजगी जाहिर कर संबंधित अधिकारियों को यह शिकायतें रीओपन कराते हुए निराकरण हेतु निर्देश दिए। उन्होंने समाधान ऑनलाईन के प्रकरणों को भी समयावधि में निराकृत करने के लिए कहा। बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों में समय से जबावदावा दर्ज कराने के निर्देश दिए।

आमजन से जुड़े मामलों का संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया जाए: कलेक्टर डॉ. सोनवणे

टीएल बैठक में कलेक्टर ने की विभागीय योजनाओं की समीक्षा

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सोमवार को आयोजित समयसीमा की बैठक में विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने कहा कि आमजन से जुड़े मामलों का संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया जाए। उन्होंने लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर उनका शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही शासन की जनहितकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचे, इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने जिले में किसानों के लिए उपलब्ध खाद की स्थिति एवं उसके वितरण की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को

निर्देश दिए कि खरीफ सीजन को देखते हुए जिले में खाद की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखी जाए तथा किसानों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय पर खाद उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि खाद वितरण में पूरी पारदर्शिता बरती जाए और ई टोकन व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को आगामी कार्यों के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग अपनी प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्यों की योजना बनाकर निर्धारित समय-सीमा में उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करे। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में लंबित भू-अर्जन, अनुकंपा नियुक्ति एवं पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए अलग से समीक्षा बैठक आयोजित की जाए।

प्रधानमंत्री मानधन श्रम योगी योजना से अधिकाधिक श्रमिकों को जोड़ने के निर्देशः

बैठक के दौरान कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने प्रधानमंत्री मानधन श्रम योगी योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को योजना का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ठेकेदारों के माध्यम से कार्य कर रहे श्रमिकों की पहचान कर उनके बैंक खाते खुलवाए जाएं तथा योजना में उनका पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि इस संबंध में सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि पात्र श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए निराकृत शिकायतों की जानकारी ली। शेष लंबित शिकायतों पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित एवं नॉन-अटेंडेड शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी शिकायत को बिना अटेंड किए लंबित न रखा जाए। कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने सार्थक एप के माध्यम से अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति की समीक्षा की। कलेक्टर ने एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों सीईओ सहित अन्य विभागीय अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की उपस्थिति की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा निर्धारित व्यवस्था का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

एआई टूल्स एवं क्लिक अप प्लेटफॉर्म का दिया प्रशिक्षण

समय सीमा बैठक के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स तथा क्लिक अप प्लेटफॉर्म के प्रभावी उपयोग संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण में आधुनिक डिजिटल तकनीकों के माध्यम से शासकीय कार्यों को अधिक सरल, त्वरित एवं व्यवस्थित ढंग से संपादित करने की जानकारी दी गई। इस दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एआई टूल्स का उपयोग कर दस्तावेज तैयार करने, सूचनाओं के संकलन, कार्यों के विश्लेषण तथा कार्यालयीन कार्यकुशलता बढ़ाने के बारे में बताया गया। वहीं क्लिकअप प्लेटफॉर्म के माध्यम से टास्क मैनेजमेंट, समय-सीमा निर्धारण, कार्यों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग एवं प्रगति की नियमित समीक्षा की प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया।

विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी के निवास पर बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भव्य स्वागत किया। फोटो: प्रवीण वाजपेई

देश में पहली बार एक साथ 12 उद्यानिकी फसलों को मिला जी आई टैग

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश ने इतिहास बनाते हुए एक साथ 12 उद्यानिकी फसलों के लिए जी आई टैग हासिल करने में सफलता हासिल की है। देश में यह पहली बार हुआ है जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में जीआई टैग मिला है। इनमें गुना का धनिया, नरसिंहपुर बरमान घाट का बेंगन, बैतूल गजरिया आम, खरगौरी की लाल मिर्च, मांडू की खुरसानी इमली, जबलपुर का मटर, सिवनी का सीताफल, मालवी आलू और गराडू, नरसिंहपुर गुड, जबलपुर सिंघाड़ा, आलीराजपुर का नूरजहां आम, बुरहानपुर का केला, इंदौरी जीरावन, रतलाम सैलाना बालम ककड़ी और छतरपुर का पान शामिल है इसके अलावा उज्जैन की इमली, आलीराजपुर का अचारी आम, मालवा का सफेद प्याज, झाबुआ का दाल पानिया, मंदसौर का देशी जीरा, बुरहानपुर की जलेबी, अशोक नगर की खिरनी को जी आई टैग दिलवाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। कृषक कल्याण वर्ष में यह एक बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों के आय को दो गुना बढ़ाने के लिए उनसे उद्यानिकी फसलों की खेती से जुड़ने का आव्हान किया है। फिलहाल 28 लाख हेक्टेयर में उद्यानिकी फसलों की खेती हो रही है।

प्रदेश में बिजली गिरने से 3 की मौत, 4 झुलसे

बैतूल में 2 लोग बहे, 2 लड़कियां नाले में गिरीं, 5 जिलों में घरों में घुसा पानी

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में मानसून के एक्टिव होते ही आंधी-बारिश का दौर तेज हो गया है। मंगलवार को हरदा में बिजली गिरने से 32 वर्षीय किसान प्रदीप राठौर की मौत हो गई। खरगोन में भी बिजली की चपेट में आने से राधेश्याम (30) और गृहिणी केनू (30) की मौत हो गई। वहीं, बैतूल के चुना गोसाई गांव में बिजली गिरने से सुखदेव यादव, उनकी पत्नी गीताबाई, बेटी संध्या और बेटा नैतिक झुलस गए। दोपहर में भोपाल के कुछ क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई।

वहीं, बैतूल के चिचोली क्षेत्र में चंपा नदी उफान पर है। रपटे को पार करते समय सिप्लाई निवासी राजेश बिहारे और दद्दू धुर्वे बाइक समेत बह गए। मंगलवार सुबह रपटे से करीब एक किलोमीटर दूर झाड़ियों में दोनों के शव मिले। बालाघाट में दोपहर 2 बजे के बाद तेज बारिश शुरू हुई। सतना और मैहर में सड़कों पर जलभराव हो गया।

देवास में तेज बारिश के दौरान दो लड़कियां स्कूटी सहित नाले में गिर गईं, लेकिन लोगों ने दोनों को बचा लिया। सीहोर के इछावर में घरों और दुकानों में पानी घुस गया। विरोध में कांग्रेस पार्षद जुनेद खान ट्यूब पर बैठकर पानी में उतरे और प्रदर्शन किया।

डिंडोरी नगर पालिका के वार्ड-8 में नाली जाम होने से घुटनों तक पानी भर गया। घरों-दुकानों में पानी घुस गया। वहीं, मैहर जिले के अमरपाटन में बिजली ऑफिस के पास गीता साकेत के कच्चे मकान में भी घुटनों तक पानी भर गया।

छिंदवाड़ा-सिवनी में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक, बुधवार को बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 इंच तक बारिश हो सकती है। इसके अलावा प्रदेश के 50 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

इनमें भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, धार, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, आगर-मालवा, शाजापुर, देवास, नर्मदापुरम, हरदा, गुना, अशोकनगर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी शामिल हैं।

इन जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। वहीं, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने का अनुमान है।

15 साल में पहली बार जून में सूखने लगा बरगी बांध

जानकार बोले-डैम के गेट खोलने पर नहीं निकलेगा पानी ; बारिश नहीं हुई तो संकट गहराएगा

जबलपुर (नप्र)। जबलपुर में मानसून की देरी और जून में सामान्य से बेहद कम बारिश का असर अब जलाशयों पर साफ दिखाई देने लगा है। शहर की लाइफलाइन माने जाने वाले बरगी बांध का जलस्तर लगातार घट रहा है। परियट और खंदारी जलाशयों में भी पानी कम होने लगा है।

बरगी बांध प्रबंधन के अनुसार बांध का जलस्तर प्रतिदिन करीब 5 सेंटीमीटर घट रहा है। कम पानी के कारण बिजली उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। दो में से एक बिजली उत्पादन यूनिट बंद कर दी गई है, जबकि दूसरी यूनिट का संचालन भी सीमित कर दिया गया है।

15 साल में सबसे खराब स्थिति- बरगी बांध प्रबंधन के अनुसार 15 जून को बांध का जलस्तर 407.85 मीटर था, जो घटकर अब 407.45 मीटर रह गया है। यानी करीब 40 सेंटीमीटर पानी कम हो चुका है। वर्तमान में बांध में केवल 12.59 प्रतिशत पानी शेष है। पिछले वर्ष इसी अवधि में जल भंडारण

करीब 22 प्रतिशत था।

जून में सिर्फ डेढ़ इंच बारिश- सामान्य तौर पर 30 जून तक जबलपुर में करीब 8 इंच बारिश दर्ज होती है, लेकिन इस वर्ष अब तक केवल करीब 1.5 इंच बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की उत्तरी सीमा अभी मंडला के आसपास है और इसके आगे बढ़ने की संभावना है।

बिजली उत्पादन पर असर- कम जलस्तर का असर बिजली उत्पादन पर भी पड़ा है। बरगी बांध की दो उत्पादन इकाइयों में से एक को 27 जून से बंद कर दिया गया है। दूसरी यूनिट, जो पहले 8 से 10 घंटे चलती थी, अब केवल 3 घंटे प्रतिदिन संचालित की जा रही है।

गेट खोलने पर भी नहीं निकलेगा पानी- एक्सपर्ट का कहना है कि बांध का जलस्तर इतना नीचे पहुंच गया है कि यदि सभी 21 गेट खोल भी दिए जाएं तो उनसे पानी बाहर नहीं निकलेगा। बांध का एक हिस्सा सूख चुका है और इसे देखने के लिए लोग भी पहुंच रहे हैं।

15 साल का रिकॉर्ड टूटा- मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष मानसून की दस्तक में भी देरी हुई है। इससे पहले 2009 में 29 जून और 2019 में 28 जून को मानसून सक्रिय हुआ था। वहीं 2013 और 2021 में मानसून 11 जून को ही पहुंच गया था।

पानी की सप्लाई और सिंचाई पर बढ़ सकता है संकट

बरगी बांध से नर्मदा का पानी जबलपुर समेत कई शहरों में पेयजल आपूर्ति के लिए भेजा जाता है। इसी बांध से निकलने वाली नहरों से जबलपुर और नरसिंहपुर में सिंचाई होती है और भविष्य में कटनी व सतना तक पानी पहुंचाने की योजना है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि जल्द अच्छी बारिश नहीं हुई तो आने वाले समय में पेयजल और सिंचाई दोनों पर संकट गहरा सकता है।

लोग देखने पहुंच रहे सूखता बांध

जबलपुर निवासी आकाश कोष्ठा ने बताया कि बरगी बांध के सूखने की चर्चा सुनकर वे मौके पर पहुंचे। उनका कहना है कि बांध का जलस्तर काफी नीचे चला गया है। नर्मदा के कई घाटों पर चट्टानें दिखाई देने लगी हैं और नदी का पानी भी पहले की तुलना में कम व गंदला नजर आ रहा है।

अल नीनो का असर भी माना जा रहा कारण

मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अल नीनो प्रभाव के कारण इस वर्ष कम बारिश की संभावना बनी हुई है। यदि जुलाई में अच्छी बारिश नहीं हुई तो मध्य प्रदेश के कई जलाशयों में जल संकट गहरा सकता है और इसका असर बिजली उत्पादन, सिंचाई तथा पेयजल व्यवस्था पर भी पड़ सकता है।

प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की विधानसभा बैतूल बनेगी नगर निगम

26 पंचायतें होंगी सीमा में शामिल, कलेक्टर ने डेटा जुटाया, विदिशा के लिए भी हो चुका है ऐलान

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले नगरीय निकाय चुनाव से पहले बैतूल को नगर निगम का दर्जा मिल सकता है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के निर्देश के बाद बैतूल कलेक्टर ने प्रस्तावित नगर निगम की सीमा में शामिल की जाने वाली 26 ग्राम पंचायतों की जांच और अध्ययन शुरू कर दिया है। कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार बैतूल को नगर निगम बनाने पर अंतिम फैसला लेगी। बैतूल को नगर निगम बनाने की चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि यह क्षेत्र भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का विधानसभा क्षेत्र है।

सीईओ ने ग्राम पंचायत के कर्मचारियों की जानकारी जुटाई- नगर निगम बनाने की प्रक्रिया के तहत जनपद पंचायत बैतूल की मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिवानी राय ने प्रस्तावित ग्राम पंचायतों में कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी जुटाई है। इसमें पंचायत सचिव, रोजगार सहायक सहित अन्य कर्मचारियों का विवरण तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट एसडीएम और एसडीओ राजस्व के माध्यम से कलेक्टर तक पहुंचाई गई है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में बैतूल विधायक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की मौजूदगी में कलेक्टर के साथ बैठक भी हो चुकी है।

छह माह में हो सकता है फैसला

अगर बैतूल को नगर निगम बनाने का फैसला होता है तो वर्ष 2027 के नगर निकाय चुनाव से पहले प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए इन गांवों को पंचायत से नगर निगम सीमा में शामिल करने का प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर कराया जाएगा। इसके बाद इन क्षेत्रों की मतदाता सूची को पंचायत से हटाकर नगर निगम की मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के लिए यह भी जरूरी होगा कि प्रस्तावित क्षेत्रों की आबादी नगर निगम के निर्धारित मापदंडों को पूरा करे।

प्रदेश में अभी 16 नगर निगम

मध्यप्रदेश में वर्तमान में 16 नगर निगम हैं। इनमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, सतना, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, रतलाम, उज्जैन, मुरैना, कटनी, देवास, खंडवा और बुरहानपुर शामिल हैं। इसके अलावा विदिशा को भी नगर निगम बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कर चुके हैं, हालांकि वहां प्रक्रिया अभी आगे नहीं बढ़ी है। अब बैतूल को लेकर अगले कुछ महीनों में फैसला होने की संभावना है।

इन 26 ग्राम पंचायतों को किया जा सकता है शामिल

बैतूल नगर निगम सीमा में शामिल करने के लिए जिन ग्राम पंचायतों को प्रस्तावित किया गया है, उनमें कढ़ाई, दनोरा (भ), बड़ोरा, आरूल, बाजपुर, भैंसदेही, खेड़ली, मरामझिरी, टेमनी, जामठी, खेड़ला, डहरगांव, खेड़ी सांवलीगढ़, महदगांव, भड़ूस, कुम्हारटेक, भोगीतेड़ा, रोढ़ा, सूरगांव, भरकावाड़ी, खंडारा, मलकापुर, मिलानपुर, बयावाड़ी, ढोड़वाड़ा और खड़ला शामिल हैं।

9 साल की बच्ची को बाइक सवार बहला-फुसलाकर ले गया

आरोपी बोला-मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूं, दिया आइसक्रीम का लालच, बालिका सुरक्षित

भोपाल (नप्र)। राजधानी के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक 9 वर्षीय बालिका को अज्ञात बाइक सवार बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। आरोपी ने खुद को बच्ची के पिता का दोस्त बताया और स्कूल छोड़ने व आइसक्रीम खिलाने का झांसा देकर उसे बाइक पर बैठा लिया। कुछ घंटे बाद बच्ची शहर के दूसरे इलाके में सुरक्षित मिल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार न्यू सुभाष कॉलोनी डी-सेक्टर निवासी 9 वर्षीय पूर्वी पंवार रोज की तरह सुबह करीब साढ़े सात बजे मंदिर में जल चढ़ाकर घर लौट रही थी। इसी दौरान एक बाइक सवार उसके पास पहुंचा और कहा कि वह उसके पिता का दोस्त है। उसने बच्ची से स्कूल छोड़ने की बात कही। मासूम उसके झांसे में आ गई और बाइक पर बैठ गई।

घरवालों ने तलाश शुरू की, सीसीटीवी में बाइक पर जाती दिखी बच्ची- जब काफी देर तक बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। आसपास खोजबीन के साथ इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। फुटेज में बच्ची एक बाइक पर बैठकर जाते हुए दिखाई दी। इसके बाद परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद अशोका गार्डन थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बच्ची ने बताया कि आरोपी ने उसे आइसक्रीम खिलाने की बात कही थी। इसी बहाने वह उसे शहर में घुमाता रहा। प्रारंभिक पूछताछ में बच्ची ने किसी तरह की मारपीट या अन्य आपराधिक घटना की जानकारी नहीं दी है। पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है।

मुख्यमंत्री ने लोकमाता अहिल्याबाई, राष्ट्र पुनरुत्थान की संकल्पना पुस्तक का किया विमोचन

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 'लोकमाता अहिल्याबाई राष्ट्र पुनरुत्थान की संकल्पना' पुस्तक का समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में विमोचन किया। मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित यह शोध संकलन बताता है कि लोकमाता, पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होल्कर का जीवन और कर्म किसी आकस्मिक महानता का परिणाम नहीं, बल्कि दीर्घ सांस्कृतिक धारा का स्वाभाविक विस्तार रहा। उनकी जीवन गाथा इस तथ्य का प्रमाण है कि भारतीय नारी संत, विदुषी, योद्धा होने के साथ-साथ कुशल शासिका भी रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा विमोचित इस शोध संकलन में कुल 19 अध्याय हैं। पुस्तक अहिल्याबाई होल्कर की दृष्टि में नारी स्वाभिमान और समाजोत्थान, सांस्कृतिक पुनर्निर्माण से राष्ट्रीय एकता,

पंचपरिवर्तन से समाज कल्याण, जीवन प्रबंधन की पाठशाला, बाल विवाह-सामाजिक कुरीति की चुनौतियाँ और समाधान पर शोध पत्रों का संकलन हैं। पुस्तक में देवी अहिल्याबाई होल्कर की राष्ट्र पुनरुत्थान की संकल्पना न्यायप्रियता और प्रशासनिक दक्षता, समग्र जीवन चिंतन, भारतीय हस्तशिल्प के उत्थान में अहिल्याबाई की भूमिका तथा महिलाओं के लिए न्याय और समानता पर शोधपरक लेख हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में लोकमाता अहिल्याबाई के अवदान के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विश्लेषण पर भी पुस्तक में एक पाठ है। पुस्तक का मूल्य 160 रूपए मात्र है। इस अवसर पर संचालक म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी श्री अशोक कड़ेल, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के निदेशक श्री चंद्रचारु त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलगुरु श्री विजय मनोहर तिवारी उपस्थित थे।

बांधवगढ़ में इंसान को मारकर खा गया बाघ

50 वनकर्मियों और 4 हाथियों ने मिलकर पकड़ा, अब 2 महीने की 'कैद'

उमरिया (नप्र)। मध्य प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से एक बेहद हैरान और डराने वाली खबर सामने आई है। पिछले हफ्ते उमरिया जिले के पनपथा बफर जोन में एक बुजुर्ग को मौत के घाट उतारने वाले 5 साल के नर बाघ को वन विभाग की टीम ने कड़े संघर्ष के बाद रेस्क्यू कर लिया है। सामान्य तौर पर बाघ इंसानों पर हमला तो करते हैं, लेकिन इस मामले में बाघ ने मृतक के शरीर के अंगों को भी खा लिया।

बाघ के इस असामान्य और डरावने बर्ताव को देखते हुए वन्यजीव विशेषज्ञों ने उसे दो महीने के लिए एक विशेष बाड़े में बंद कर दिया है, जहां उसके व्यवहार पर पैनी नजर रखी जा रही है।

4 ट्रेंड हाथियों और 50 वनकर्मियों ने मिलकर घेरा- यह खौफनाक घटना तब सामने आई जब 60 वर्षीय बुजुर्ग अन्नू रजक उत्तर पाल्हा

वन क्षेत्र में महुआ के बीज बीनने गए थे। जब वे घर नहीं लौटे, तो ग्रामीणों और परिजनों ने खोजबीन शुरू की, जिसके बाद जंगल के भीतर उनका क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ। घटना के बाद हरकत में आए वन विभाग ने 50 से अधिक जवानों और 4 प्रशिक्षित हाथियों (लक्ष्मण, सूर्या, गणेश और सुंदरगज) की मदद से एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। घने जंगलों और झाड़ियों में कई घंटों तक छिपे रहने के बाद जैसे ही बाघ बाहर निकला, वन्यजीव पशु चिकित्सकों की टीम ने उसे ट्रेंकुलाइज कर दिया।

खून और जैविक नमूनों की होगी जांच- बाघ के इस हिंसक बदलाव की वजह जानने के लिए डॉक्टरों की टीम ने उसके ब्लड सैंपल्स और अन्य बायोलॉजिकल नमूने एकत्र किए हैं, जिन्हें प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट और दो महीने की निगरानी के आधार पर ही इस बिग कैट के भविष्य का फैसला होगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में इस साल बाघों के हमलों में जान गंवाने वाले नागरिकों का आंकड़ा बढ़कर 22 हो गया है, जिसने वन विभाग और वन्यजीव प्रेमियों की चिंताएं बढ़ा दी हैं।

इंसान को मारकर खाना सामान्य नहीं : एक्सपर्ट्स हैरान

स्वास्थ्य परीक्षण के बाद बाघ को मगधी रेंज के बहेरहा एन्क्लोजर में शिफ्ट कर दिया गया है। वन्यजीव वैज्ञानिकों और अधिकारियों के मुताबिक, बाघों का यह व्यवहार उनके मूल स्वभाव के विपरीत है, जिसके पीछे किसी बीमारी या मानसिक विकृति की आशंका भी हो सकती है। बाघ का इंसानों पर हमला करना प्राकृतिक हो सकता है, लेकिन किसी इंसान को मारना और फिर उसके शरीर के अंगों को खा जाना बाघों का सामान्य व्यवहार नहीं है। यह बेहद चिंताजनक है। हमने उसे एक सुरक्षित बाड़े में शिफ्ट कर दिया है, जहां अगले दो महीनों तक उसके व्यवहार, आक्रामकता और मानसिक स्थिति का बारीकी से अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद ही तय होगा कि उसे वापस जंगल में छोड़ा जाए या चिड़ियाघर भेजा जाए।